सरकार में सैद्धांतिक सहमति, घोषणा बाकी

जुलाई में 5 फीसदी डीए की बकाया किस्त देने की तैयारी

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

नगरीय निकायों के चुनावों के पहले यानी जुलाई में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ते की बकाया किस्त का भुगतान करने की तैयारी हो गई है। इस पर सरकार की सैद्धांतिक सहमति तो है सिर्फ अधिकारिक घोषणा होना बाकी है। हालांकि केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच महंगाई का अंतर 5 फीसदी से बढ़कर जुलाई में 9 फीसदी हो जाएगा। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को जुलाई में वर्ष 2020 जनवरी के बकाया 4 फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा की है। बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मियों को 17 फीसदी तो राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर 12 फीसदी डीए मिल रहा है। इस तरह 21 महीनों से प्रदेश के 4.50 लाख कर्मचारियों को 5 फीसदी डीए का नुकसान हो रहा है। इस साल के बजट में सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में स्थापना व्यय में 9107 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रावधान किया है। स्थापना व्यय में ज्यादा बढ़ोतरी की वजह सरकार के द्वारा कर्मचारियों का बकाया हिसाब-किताब चुकता करना है।

शेष | पेज 10 पर

BadriGautam

जुलाई में 5 फीसदी डीए की बकाया...

21 हजार करोड़ राजस्व घाटे का अनुमान : राज्य सरकार का पिछले दो सालों में राजस्व घाटे का बजट रहा है। इसमें 2020-21 में राजस्व घाटा 21 हजार करोड़ रुपए और 2021-22 में 8 हजार करोड़ रुपए राजस्व घाटे का अनुमान है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष में सरकार को खर्चे चलाने के लिए 49 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ेगा।

अब 50 साल की आयु वाले शिक्षकों की गोपनीय जांच करेगा विभाग

भास्कर न्यूज़ | मुरैना

शिक्षा विभाग के ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके हैं, अब उनके कार्य की गोपनीय जांच होगी। जांच में अक्षम, अयोग्य और भ्रष्ट पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि उन्हें सेवानिवृत्त भी किया जा सकता है। विभाग एक जनवरी 2021 की स्थिति में 20 वर्ष सेवा या 50 साल की आयु के शिक्षकों की सूची तैयार कर रहा है। शिक्षा विभाग अब अपने अधिकारियों, कर्मचारियों की सूक्ष्म रूप से जांच करेगा। इसके लिए संभाग व जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी जांच कर रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपेगी। विभाग पूर्व में निर्देश दे चुका है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है या जिनकी 20 वर्ष की नौकरी पूरी हो गई है, ऐसे शासकीय शिक्षकों के कार्यकाल की जांच की जाए। अगर शासकीय सेवक की स्थिति अक्षम, अयोग्य पाई जाती है या कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वह सिद्ध होता है तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।

Badri Gautam

काल्पनिक वेतन वृद्धि को हाईकोर्ट में चुनौती

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर| मप्र हाईकोर्ट में राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी गई काल्पनिक वेतन वृद्धि को चुनौती दी गई है। याचिका में काल्पनिक वेतन वृद्धि को निरस्त कर वास्तविक वेतन वृद्धि दिए जाने की माँग की गई है। मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रांताध्यक्ष उदित भदौरिया की ओर से दायर याचिका पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है। लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि वार्षिक वेतन वृद्धि पाना कर्मचारियों का अधिकार है। मध्यप्रदेश सरकार ने जुलाई 2020 में मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि और 5 प्रतिशत डीए को रोक दिया गया था। सरकार ने इसे काल्पनिक वेतन वृद्धि का नाम देकर कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास किया। जुलाई 2021 में फिर कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का मिलना है। समिति के रॉबर्ट मार्टिन ने बताया कि याचिका में मुख्य सचिव, वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिवों को पक्षकार बनाया गया है।पी-3

Badri Gautam

याचिका कहा- सरकार का निर्णय दुर्भावनापूर्ण, साढ़े पांच लाख कर्मचारियों को लाभ से रखा वंचित

वेतनवृद्धि के लिए सरकार के खिलाफ न्यायालय पहुंचे कर्मचारी

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

कोरोना को आधार बनाकर मप्र सरकार द्वारा रोकी गई 2 वेतनवृद्धियों की बहाली के लिये अधिकारी कर्मचारी ने न्यायालय की शरण ली है। उच्च न्यायालय जबलपुर में दाखिल की गई इस याचिका में वेतनवृद्धि रोकने के आदेश को अवैध बताते हुए कहा गया है कि सरकार ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रदेश के करीब साढ़े पांच लाख कर्मचारियों को लाभ से वंचित किया गया है। यह याचिका जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के माध्यम से उदित भदौरिया और अरूण द्विवेदी के द्वारा दायर की गई है।

मामले में पैरवी के लिये नियुक्त किये गये अधिवक्ता अशोक श्रीवास्वत रूमी ने मध्य स्वदेश को बताया कि न्यायालय ने याचिका को पंजीकृत कर ली है। बहस के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश के साढ़े पांच लाख कर्मचारियों से जुड़े इस मामले में अदालत का रूख क्या है। क्योंकि इसमें स्पष्टतः कहा गया है कि दुर्भावानापूर्ण तरीके से अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतिवर्ष मिलने वाली वेतनवृद्धियों को जहां रोका गया है, वहीं दूसरी ओर यह भारतीय संविधान और विधिक नियमों का उल्लंघन भी है। बता दें कि मप्र सरकार ने केंद्र सरकार के कोरोना संक्रमण गाइड लाइन व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 1/1 का उल्लेख करते हुए एक जुलाई 2020 और एक जुलाई 2021 से मिलने वाली वेतनवृद्धि का निर्धारण काल्पनिक दर्शाते हुए कर्मचारियों को इसके भुगतान से वंचित कर दिया गया है।

विकास के लिए नहीं कर्मचारियों के लिए धन की कमी!

मप्र के अधिकारी-कर्मचारियों की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों के स्वायत का भुगतान करने में धन की कमी बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ो के विकास कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है। जबकि आपदा प्रबंधन के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों में कहीं भी वेतनवृद्धि रोकने का उल्लेख नहीं है।

सरकार को चाहिये छह सौ करोड़

वित्त विभाग से जुड़े अधिकारिक सूत्रों पर विश्वास किया जाय तो दो वेतनवृद्धि ऐरियर्स सहित यह राशि करीब छह सौ करोड़ तक चली जाएगी। क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी को औसतन 50 हजार रूपये का लाभ होना है। प्रदेश में ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की संख्या साढ़े 5 लाख है। सेवा इतिहास में यह पहला अवसर बताया जा रहा है, जबकि शासकीय कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है।

चेतावनी को सरकार ने नहीं लिया संज्ञान

जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के माध्यम से उदित भदौरिया ने बताया कि इस मामले में बीते 27 मार्च को सरकार को सूचना पत्र जारी किया गया था, लेकिन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यवाही तो दूर इसे संज्ञान में लेने की जरूरत नहीं समझी। लिहाजा हक के इस संघर्ष में न्याय के लिये याचिका के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं बचा है।

पुलिस के समान पद प्रभार नहीं चाहते मंत्रालयीन कर्मचारी

भोपाल। पुलिस के समान मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी पद प्रभार नहीं चाहते हैं। अपनी मांगों की ओर यह कहते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक का। शुक्रवार को जारी बयान उन्होने कहा कि प्रत्येक आठ वर्ष के बाद अगला पदनाम और अगला वेतनमान मिलने का प्रावधान लागू होना चाहिये। जिससे मंत्रालय के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को समान वेतनमान दिया मिल जाय। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया है कि शासन के समक्ष यह पिछले समय में कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य प्रशासनिक सेवा एवं कोष व लेखा की भांति उच्च पद पर क्रमोन्नति देने संबंधी संशोधन करने की मांग पर अडिग है। बता दे कि पुलिस विभाग ने बिना तनख्वाह बढ़ाये ही निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को उपपुलिस अधीक्षक बना दिया है। यही वजह है कि पुरानी और कम तनख्वाह में नया पद और बड़ी जिम्मेदारी पाकर इनमें से कई अधिकारी खुश नहीं बताये जाते हैं। जबकि ओहदे से इन सभी को राजपत्रित अधिकारी के अधिकार मिल गये है।

Badri Gautam

अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले के लिए एक पद रखो रिक्त

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवार के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में एक पद रिक्त रखा जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। याचिका की सुनवाई 16 अप्रैल को नियत की गई है। राजगढ़ निवासी किशोर वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परीक्षा का परिणाम 28 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था। मेरिट में उसका 40वाँ स्थान था। 23 जून 2020 को आयुक्त लोकशिक्षण ने आदेश जारी किया कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवार उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आदेश के जरिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी अपात्र घोषित कर दिया गया।

Badri Gautam

याचिका में कहा गया कि परीक्षा के नियम और विज्ञापन में अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों को अपात्र घोषित करने की शर्त नहीं लागू की गई है। अधिवक्ता बृंदावन तिवारी ने तर्क दिया कि इस मामले में डिवीजन बैंच ने 12 अक्टूबर 2020 को नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए याचिकाकर्ता के लिए शिक्षक भर्ती में एक पद रिक्त रखने का आदेश दिया है। पी-4

शिक्षकों ने एक बार फिर से सरकार पर पदनाम का दबाव बनाया

अगले पद पर प्रभार देकर मंत्रालय में पुलिस की पदोन्नति मंजूर नहीं

शिक्षा विभाग में पदनाम क्यों नहीं ?

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मचारियों को अगले पद का प्रभार देकर जो पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाई गई है। मंत्रालय में इसको लेकर असंतुष्टि जाहिर की गई है। इधर प्रदेश में शिक्षकों का कहना है कि सरकार पदनाम के विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। पुलिस के साथियों को अगले पद का प्रभार देकर पदोन्नति की भरपाई की गई है। पुलिस के साथी इस तरह का प्रभार मिलने से प्रसन्न हैं, परंतु मंत्रालय में हम इस तरह का प्रभार नहीं चाहते हैं। संगठन द्वारा शासन के समक्ष बार बार स्पष्ट कर दिया है। पत्र भी लिखा गया कि मंत्रालय सेवा में राज्य प्रशासनिक सेवा और कोष एवं लेखा की भांति उच्च पद पर क्रमोन्नति देने संबंधी संशोधन करने की मांग की है और हम उसी पर अडिग हैं। प्रत्येक 08 वर्ष के बाद अगला पदनाम और अगला वेतनमान मिलने संबंधी प्रावधान लागू होना चाहिए। इससे सभी वर्गों को समान रूप से लाभ मिलेगा और आपसी विवाद समाप्त होकर सभी मंत्रालयीन साथी एक सूत्र में बंधेंगे।

सीएम से की जाएगी मुलाकात

इधर पदनाम को लेकर एक बार फिर शिक्षकों ने सरकार पर दबाव बनाया है। शिक्षकों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई थी। उसके समक्ष प्रस्ताव भेजे गये थे, लेकिन शिक्षकों को पदनाम नहीं मिल पाया है। मप्र सहायक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक सुभाष शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों का बड़ा आर्थिक नुकसान किया गया है।

स्वयं सीएम की घोषणा है कि सहायक शिक्षकों को शिक्षक का पदनाम दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में सरकार पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं है। फिर भी अधिकारी पदनाम देने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर रहे हैं। शर्मा का कहना है कि इस संबंध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की जाएगी। क्योंकि पदनाम की प्रतीक्षा करते हुए प्रतिमाह शिक्षक रिटायर्ड हो रहे हैं।

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में असमंजस, स्थिति स्पष्ट करने पर अड़े बेरोजगार

भोपाल। विद्यालयों में 24 हजार 200 शिक्षकों के पद भरने के लिए सरकार द्वारा बजट मे किये गये प्रावधान को लेकर वह बेरोजगार अभ्यार्थी सामने आये हैं, जिन्होंने पिछले साल शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से लेकर अन्य अधिकारियों को पत्र भी दिया गया। बेरोजगारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे रंजीत गौर का कहना है कि सरकार ने 24 हजार 200 पदों को भरने के लिए इस सत्र के बजट में प्रावधान किया है। दूसरी ओर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उच्च माध्यमक शिक्षकों के 15 और माध्यमिक शिक्षकों के 5 हजार 670 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। अब बजट के अनुसार तो कुल 24 हजार 200 पदों पर ही भर्ती होना चाहिए। सरकार ने यह पद स्वीकृत तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग पात्र अभ्यार्थियों द्वारा पिछले कई दिनो से की जा रही है, लेकिन परीक्षा के बाद भर्ती कई सालों से नहीं हो पाई है।

बेरोजगारों ने सीएम से लेकर अन्य अधिकारियों को दिया पत्र

मातृभाषा के पदों में तत्काल हो वृद्धि

एक बार फिर मातृभाषा के पदों में वृद्धि की मांग उठी है। महिला बेरोजगार संघ की अध्यक्ष ममता निगम का कहना है कि पिछले वर्ष 2019 में जो परीक्षा कराई गई थी। उसमें सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हिंदी एवं संस्कृत जैसे पदों पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है कि मातृभाषा के पद सरकार को तत्काल बढ़ाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हजारों पद हिंदी और संस्कृत के रिक्त पड़े हैं। इन पदों को भरने में विभाग की कोई रूचि नही दिखाई दे रही है। इसके लिए कई बार सरकार को पत्रभी प्रेषित किए गए है। फिर भी कोई ध्यान नही दिया जा रहा है।

Badri Gautam

मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों में पारदर्शिता लाने एक्शन में आई प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा-नियम अनुसार जानकारी नहीं दी तो समाप्त होगी मान्यता

भोपाल ■ गौरीशंकर चौरसिया

मध्यप्रदेश में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रति राज्य सरकार एक्शन में दिख रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कहा है कि तमाम सुविधाएं ले रहे संगठनों ने यदि नियम के अनुसार जानकारी नहीं दी तो मान्यता समाप्त हो जाएगी।

बताना होगा कि पिछले कुछ समय से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों में विवाद की स्थिति बनी हुई है। कारण भी है कि जिस संगठन के पास मान्यता है उसको तबादला अवधि में छूट से लेकर अवकाश सहित अनेक सुविधाएं सरकार की ओर से मिल रही है। जबकि संगठनों के लिए धारा 27 और 28 बनाई गई है। इसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी संगठन को प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या अनुपात से 33 प्रतिशत सदस्यता की सूची पारदर्शी तरीके से जमा करना अनिवार्य है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों में कितना सदस्यता शुल्क आया है इसको भी सार्वजनिक करना जरूरी है। सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि रजिस्टर्ड फर्म सोसाइटी के माध्यम से प्रत्येक संगठन को यह काम करना चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह संदेह के घेरे में है।

सामान्य प्रशासन विभाग की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि सरकार द्वारा मान्यता देने के बाद भी आए दिन एक ही संगठन में तीन से चार लोग विसंगतियों की शिकायत कर रहे हैं। संगठनों के लोग ही यह शिकायत कर रहे हैं कि नियम के अनुसार चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। नियम यही है कि कर्मचारी संघों में वोट से चुनाव होना चाहिए, परन्तु बंद कमरों में चंद चहेते लोगों से तालियां बजवाकर चुनाव करवा लिए जाते हैं। नतीजतन अब जांच करना मजबूरी बन गई है। अगर नियम के अनुसार कर्मचारी संगठनों में काम होते नहीं पाया गया तो इनकी मान्यता भी समाप्त की जाएगी।

मान्यता प्राप्त संघ में ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर पर ठाठ बाट

प्रदेश के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों में राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों के ठाट बाट कोई कम नहीं है। अगर ब्लॉक और तहसीलो में देखें तो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव को 4 साल तक तबादलो में पूरी तरह छूट मिलती है। 4 वर्ष तक इन्हें कोई नहीं हटा सकता है चाहे यह काम करें या न करें। यही व्यवस्था जिला संभाग और प्रदेश स्तर की है। इसके अलावा ब्लॉक तहसील से लेकर राज्य स्तर पर अवकाश के दिनों में भी बड़ी छूट मिलती है। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की परामर्श दात्री समितियों में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को बतौर अतिथि आमंत्रित करने की भी सुविधा है। सामान्य प्रशासन विभाग की पीड़ा यह है कि मान्यता मिलने के बाद भी कर्मचारी संघों के बीच से आ रही शिकायतें सरकार के लिए सिरदर्द का कारण बन गई है। इस कारण अब जांच करवाना जरूरी हो गया है।

लगातार वोट से चुनाव करवाने की होती रही मांग

वरिष्ठ कर्मचारी नेता मोहन अय्यर कहते हैं कि हम लंबे समय से यही मांग करते आ रहे हैं कि जब कर्मचारी संगठनों को सरकार की ओर से सभी सुविधाएं मिल रही हैं तो इनमें वोट से चुनाव होना चाहिए। अय्यर कहते हैं कि एक ही स्वयंभू अध्यक्ष बना रहना कहीं से भी उचित नहीं है। वही वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरारी लाल सोनी का कहना है कि सरकार को तत्काल मानता प्राप्त कर्मचारी संघ की जांच करवाना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में हो रहे आपसी विवाद प्रदेश सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं।

बदल सकती है मुख्यमंत्री की कर्मचारी संगठनों से वार्ता की तिथि

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कि कर्मचारी संगठनों से वार्ता की तिथि में बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा 3 एवं 4 अप्रैल को संगठनों से वार्ता करने का समय तय किया गया था। अब 3 अप्रैल यानी शनिवार को मुख्यमंत्री की अधिक व्यस्तता है। जबकि 4 अप्रैल को रविवार होने के कारण टोटल लॉकडाउन है। इस कारण सोमवार या मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारी संगठनों से वार्ता कर सकते हैं।

इनका कहना

कर्मचारी संगठनों की नियम अनुसार जानकारी जुटाने की जवाबदारी रजिस्टर्ड फर्म सोसाइटी की है, लेकिन आए दिन शिकायतें आ रही हैं इस कारण हम जांच करवा रहे हैं कि आखिर संगठनों की क्या स्थिति है।

इंदर सिंह परमार राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन विभाग

Badri Gautam

हाई कोर्ट पहुंचा काल्पनिक वेतन वृद्धि का मामला

जबलपुर । राज्य सरकार के कर्मचारियों ने काल्पनिक वेतन वृद्धि को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है।

मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रांताध्यक्ष उदित भदौरिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वार्षिक वेतन वृद्धि पाना कर्मचारियों का अधिकार है। सरकार ने जुलाई 2020 में वार्षिक वेतन वृद्धि और पांच प्रतिशत डीए को रोक दिया गया था। उसे काल्पनिक वेतन वृद्धि का नाम दिया गया था। याचिका में काल्पनिक वेतन वृद्धि के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। -नप्र

Badri Gautam

109 केन्द्रों में होगी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

भास्कर न्यूज़ | सतना

शैक्षणिक सत्र 2020-21 की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जिला शिक्षा कार्यालय से भेजी गई परीक्षा केन्द्रों की सूची को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार 7 परीक्षा केन्द्र अतिरिक्त तौर पर बनाए गए हैं। कुल 109 परीक्षा केन्द्रों में बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिला शिक्षा कार्यालय से 115 परीक्षा केन्द्रों

सहित 5 अतिरिक्त केन्द्रों की सूची मंडल को भेजी गई थी, जिसे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निरस्त कर दिया गया था। बाद में दोबारा परीक्षा केन्द्रों का प्रस्ताव अनुमोदन पश्चात भेजा गया था। परीक्षा में इस बार 10वीं एवं 12वीं के छात्रों को मिलाकर कुल 52 हजार छात्र परीक्षा देंगे।

घटी है छात्र संख्या

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों में 15 फीसदी की गिरावट आई है। बीते सत्र में आयोजित की गई 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में लगभग 65 हजार 166 छात्रों का पंजीयन किया गया था। इस बार इनकी संख्या 52 हजार 839 में ही अटक गई है। कुल 12 हजार 327 छात्र विगत वर्ष की तुलना में इस बार कम हुए हैं। यही वजह है कि बोर्ड द्वारा 115 परीक्षा केन्द्रों की जगह 109 केन्द्रों को ही मंजूरी दी गई है।

फैक्ट फाइल

सत्र 2020-21	
» नियमित कक्षा 10वीं	30 हजार 332
» नियमित कक्षा 12वीं	18 हजार 655
» स्वाध्यायी 10वीं में	2245
» स्वाध्यायी 12वीं में	1607
सत्र 2019-20	
» नियमित कक्षा 10वीं	36017
» नियमित कक्षा 12वीं	23124
» स्वाध्यायी 10वीं	3390
» स्वाध्यायी 12वीं	2635

प्रायोगिक परीक्षा 15 से

जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा 15 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 10वीं एवं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विषयमान से छात्रों की सूचना जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। कार्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त करने के लिए शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। बताया गया कि एक सप्ताह में सूची बनकर तैयार हो जाएगी और सम्बंधित शिक्षकों को आदेश भी जारी हो जाएंगे।

Bhari Gautam

प्रीबोर्ड-बोर्ड परीक्षाएँ देने वाले विद्यार्थियों को होगी आसानी

पहल : एमपी बोर्ड ने जारी की 500 क्वेश्चन्स की नई प्रश्न बैंक

हमारे प्रतिनिधि | जबलपुर

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 500 प्रश्नों की नई प्रश्न बैंक जारी कर दी है। इसमें मौजूद प्रश्न बदले हुए हैं। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर प्रीबोर्ड और बोर्ड परीक्षाएँ होंगी। वर्तमान में शहर के स्कूल कोरोना के चलते बंद हैं। हालाँकि सूत्र बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आदेश न आने तक फिलहाल यही माना जा रहा है कि अपनी तय तारीख पर ही बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ आयोजित होंगी। माशिमं ने जो प्रश्न बैंक जारी की है उसे विद्यार्थियों को प्रिंट निकालकर देने कहा जा रहा है या फिर वॉट्सअप भी शिक्षक कर सकते हैं ताकि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को पेपर हल करने में दिक्कत न आवे। बताया जा रहा है कि एक या दो विषयों की प्रश्न बैंक को छोड़कर सभी विषयों की प्रश्न बैंक जारी की जा चुकी है।

नई प्रश्न बैंक में ये हुआ बदलाव

नई प्रश्न बैंक में विद्यार्थियों को अंकों के साथ ही अध्याय के मुताबिक अलग-अलग प्रश्न मिल रहे हैं। इससे परीक्षा की तैयारियाँ करना आसान होगा। 12 अप्रैल से प्री बोर्ड होने वाली है। इधर प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए माशिमं ने आदेश जारी किया है कि परीक्षा होने के दूसरे दिन ही कॉपियों का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों को दिखाया जाए, जिससे अपनी गलती सुधारकर छात्र बोर्ड की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें।

Badri Gautam

सर, बोर्ड परीक्षाएँ तय समय पर होंगी या डेट आगे बढ़ जाएगी

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर हेल्पलाइन सेवा को सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक खोल दिया है। इन 12 घंटों के दौरान भोपाल में बैठे काउंसलर्स टोल फ्री नंबर 18002330175 पर विद्यार्थियों और अभिभावकों द्वारा पूछे प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हेल्पलाइन पर ज्यादा विद्यार्थी यही पूछ रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षाएँ समय पर होंगी या फिर तारीख आगे बढ़ जाएगी। इस पर उन्हें यही जवाब दिया जा रहा है कि फिलहाल परीक्षाओं की तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए अपनी तैयारियाँ विधिवत जारी रखें। जो 500 प्रश्नों की प्रश्न बैंक तैयार की गई है उससे तैयारियाँ करना बेहतर होगा। पी-4

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनावश्यक भीड़ न लगाएँ : निर्देश

कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शिक्षक या कर्मचारी अनावश्यक रूप से डीईओ कार्यालय में भीड़ न लगावें। यदि कार्यालय आना आवश्यक हो तो पहले बीईओ और संकुल प्राचार्य से इसकी अनुमति ली जाए। यहाँ तक की स्वयं ये दोनों अधिकारी भी बिना आवश्यक कार्य के कार्यालय न आवें। यदि कोई कार्य कार्यालय आकर ही संपन्न हो सकता है, तो इसके लिए ई-मेल अथवा वाट्सएप के माध्यम से स्वीकृति ली जाए। साथ में अनुमति पत्र लाना अनिवार्य होगा। सभी आगंतुकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, दो गज की दूरी को जरूरी बताया गया है। आवश्यक डाक आवक कक्ष में ही जमा होगी।

bhaskarhindi.com
विज़िट कीजिए, अपडेटेड रहिए.

बीते साल की तरह स्कूलों में नया सत्र फिर से शुरू हो रहा ऑनलाइन

हमारे प्रतिनिधि, जबलपुर | कोरोना संक्रमण के कारण राज्य शासन ने 15 अप्रैल तक स्कूल-कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया है। कॉलेजों में तो अभी परीक्षाएँ होनी बाकी हैं, लेकिन स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के परिणाम आ चुके हैं। इसलिए सरकारी व गैर सरकारी दोनों स्कूलों में बीते साल की भाँति इस बार भी नया सत्र ऑनलाइन शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है, ताकि विद्यार्थियों का पढ़ाई से लिंक न टूटने पाए। स्कूल खुलने के आदेश आते ही आगे की पढ़ाई कक्षाओं में ऑफलाइन तरीके से शुरू की जाएगी। निजी स्कूल कम्प्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पर विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्यापन कराते हुए नया सत्र शुरू कर रहे हैं।

सीबीएसई : नए सत्र 2021-2022 के लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का सिलेबस जारी

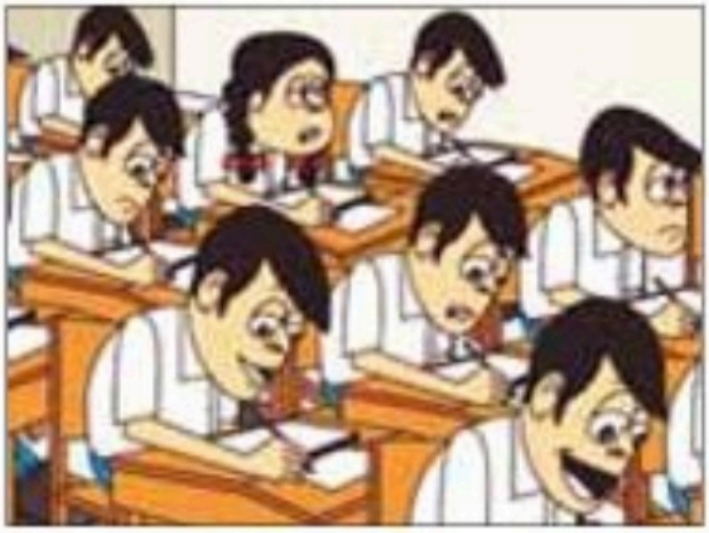

हरिभूमि, जबलपुर

स्कूलों को अप्रैल 2021 से नया सत्र शुरू करने के निर्देश जारी करने के बाद अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अकादमिक सत्र 2021-2022 के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए जारी किए गए नए सिलेबस को विद्यार्थी cbseacademic.nic.in पर जाकर सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। हालांकि बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के सिलेबस में कोई कटौती नहीं की है। यानी, स्टूडेंट्स को इस बार परीक्षाओं के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना होगा।

शिक्षकों और बच्चों को शेयर करें सिलेबस

बोर्ड ने कहा है कि स्कूल सभी शिक्षकों और बच्चों के साथ सिलेबस शेयर करें। सिलेबस बच्चों को पढ़ाने से पहले शिक्षक खुद इसकी अच्छे से स्टडी कर लें। स्कूल के प्रमुख सिलेबस की शुरुआत में दिए गए महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर शिक्षकों से चर्चा कर सकते हैं। छात्रों को बता दें कि, पिछले शैक्षणिक सत्र का संशोधित-घटा हुआ सीबीएसई सिलेबस नए शैक्षणिक वर्ष में लागू नहीं होगा। इसलिए, छात्र नए पाठ्यक्रम को जरूर चेक करें।

Badri Gautam

फीस के लिए रिजल्ट रोक रहे निजी स्कूल

भोपाल। फीस को लेकर राजधानी में कुछ निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। पालक महासंघ मप्र ने निजी स्कूलों पर फीस जमा न होने की स्थिति में विद्यार्थियों का रिजल्ट रोकने के आरोप लगाए हैं और इसका विरोध जताया है। पालक महासंघ का कहना है कि इस प्रकार से फीस के लिए बच्चों का रिजल्ट रोकना गलत है, जबकि इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर चुका है। पालक महासंघ इसको लेकर जल्द ही स्कूल शिक्षा मंत्री सहित विभाग के आला अधिकारियो से मुलाकात करेगा।

Badri Gautam

20 जून को होगी कामेडके यूनी-गेज प्रवेश परीक्षा

भोपाल। कामेडके युगेट एंड यूनी-गेज प्रवेश परीक्षा 20 जून 2021 को एक संयुक्त परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। यह प्रवेश परीक्षा कर्नाटका प्रोफेशनल कॉलेजेस फाउंडेशन ट्रस्ट तथा यूनी-गेज के सदस्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों में बीई, बीटेक में प्रवेश हेतु आयोजित की जाएगी। सम्पूर्ण भारत के 150 से भी अधिक शहरों में 400 से भी अधिक टेस्ट सेंटरों में इन प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष इस परीक्षा में 80000 से अधिक विद्यार्थियों के बैठने की संभावना है। परीक्षा के लिए आवेदकों को कामेडकेडॉटओआरजी या यूनी-गेज.डॉटकॉम पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 22 मार्च 2021 से 20 मई 2021 तक जारी चलेगी। डॉ कुमार, एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कामेडके ने कहा, इंजीनियरिंग की शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक हमेशा से एक अग्रणी स्थान रहा है। वर्ष दर वर्ष हम कर्नाटक के बाहर से इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा होते देख रहे हैं। पिछले 15 सालों से कामेडके राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उत्कृष्ट और सफल तरीके से इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। पी. मुरलीधर, सीईओ, इरा फाउंडेशन ने कहा, कोरोना को देखते हुए इस वर्ष हमने अपने सुरक्षा मानकों को और अपग्रेड किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर सेंटर पूरी तरह सेनेटाइज्ड हो और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए केवल 50 प्रतिशत विद्यार्थियों के हिसाब से बैठक व्यवस्था की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कामेडके युगेट एंड यूनी-गेज परीक्षा भारत की दूसरी सबसे बड़ी मल्टी यूनिवर्सिटी प्राइवेट इंजीनियरिंग परीक्षा बन चुकी है। जिसमे 180 से अधिक संस्थान तथा 30 से अधिक यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश देती हैं। सम्पूर्ण आवेदन व परीक्षा प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी।

Badri Gautam

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला 12 को

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं पर कोरोना का साया पड़ता दिखाई दे रहा है। राजधानी सहित प्रदेश में अप्रैल माह में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से बोर्ड अब 10वीं, 12वीं हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। बता दें कि 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला 12 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में लिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री बैठक के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौजूदा हालातों पर कलेक्टरों से चर्चा करेंगे। 9वीं व 11वीं की 13-14 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। बोर्ड यह परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से कराने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि विभाग को तय समय पर परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन संक्रमण की स्थिति और बिगड़ती है तो बोर्ड परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार हो सकता है, लेकिन इस पर 15 अप्रैल के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जबकि 9वीं, 11वीं की परीक्षा कैसे कराएं, इसे लेकर विकल्पों पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण परीक्षाओं की तैयारी पर असर पड़ रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में 15 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का निर्णय हो चुका है। ऐसी स्थिति में कक्षा 9वीं व 11वीं की लिखित परीक्षाओं की तैयारी नहीं हो पाएगी। ऐसे में सरकार दोनों परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से कराने पर विचार कर रही है। यानी विद्यार्थी घर बैठे ही पेपर हल करेगा। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग पहले ही स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष एवं पोस्ट ग्रेजुएट द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं इसी पद्धति से कराने का निर्णय ले चुका है।

जनरल प्रमोशन देने से इनकार

हालांकि बोर्ड तय कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। यदि 15 अप्रैल तक कोरोना संक्रमण कुछ कम हुआ या स्थिरता आईए तो परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर कोरोना से बचाव के प्रबंध करने में निर्देश पहले ही जारी कर चुका है। परीक्षा केंद्र बढ़ाने के निर्देश मंडल ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नई व्यवस्था भी बनाई है। इसकी वजह यह है कि सरकार जनरल प्रमोशन देने से इनकार कर चुकी है।

Badri Gautam

हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, त्योंथर कॉलेज को केन्द्र बनाने की अनुशंसा

याचिकाकर्ता समाजसेवी ने जताई आपत्ति

जागरण, रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा त्योंथर के शासकीय कालेज को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस बात को लेकर पूर्व मे इस संबंध में याचिका दायर करने वाले समाजसेवी वीके माला ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने त्योंथर कॉलेज को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने का विरोध किया है व विवि प्रबंधन पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप भी लगाया है। समाजसेवी बीके माला के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर त्योंथर सहित अन्य कई कालेजों का परीक्षा केन्द्र तोड़ा गया था। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि भविष्य में कभी भी इन केन्द्रों में परीक्षा आयोजित कराने की रूपरेखा बनाई जाती है तो विश्वविद्यालय पहले कोर्ट को सूचित करेगा। माला ने कहा कि इस तरह के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने गलत रूप से निर्णय ले लिया। किसी प्रकार की कोई सूचना हाईकोर्ट को भी नहीं दी गई। बताया कि उनके द्वारा वर्ष 2014-15 में जनहित याचिका क्रमांक 536/2014 इस संबंध में हाईकोर्ट में दायर की गई थी जिसमें शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए थे। शासन ने भी इस संबंध में आदेश जारी किए है कि इस प्रकार के नकालची महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाए व याचिकाकर्ता बीके माला को भी सुना जाए। पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई थी लेकिन वहां इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसलिए इस प्रकार के महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाना अपने आप में बड़ा प्रश्नचिंह है। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25 मार्च 2021 को नियम विरूद्ध निर्णय लिया गया है। यहां हैरानी की बात यह है कि कुलपति द्वारा भी हाईकोर्ट के आदेश सहित अन्य आदेशों का अवलोकन नहीं किया गया। मनमानी तरीके से इस महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करना ही अनुचित है।

Badri Gautam

नर्सिंग होम नियमित करने में फीस का पेंच बीएमसी अब तक तय नहीं कर पाया

आठ महीने से चल रही प्रक्रिया

जागरण प्रतिनिधि, भोपाल

शहर में आवासीय इलाकों में खुले नर्सिंग होम्स को वैध करने में लगा फीस का पेंच आठ महीने में भी हट नहीं पाया है। यह तय नहीं हो पाया है कि कितना शुल्क लिया जाए। राज्य शासन ने खुद इसका निर्णय लेने की बजाय नगर निगम को ही यह जिम्मा सौंप दिया। निगम प्रशासन भी एक महीने में शुल्क फाइनल नहीं कर पाया है। लीज की शर्तों का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों में नर्सिंग होम व अस्पताल खुल गए हैं। इससे आसपास के रहवासियों को पार्किंग समेत अन्य परेशानी होती हैं। ऐसे में नर्सिंग होम को नियमित करने की कवायद चार-पांच साल पहले शुरू की गई थी। तब इसका नर्सिंग होम संचालकों ने काफी विरोध किया था। इस कारण कुछ समय के लिए यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। फिर टाउन एंडी कंट्री प्लानिंग ने सितंबर, 2018 में मास्टर प्लान 2005 में संशोधन कर नर्सिंग होम को वैध करने के लिए नियम बनाए थे।

शुल्क पर संचालक अड़े तो शासन से मांगा मार्गदर्शन

नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी ने करीब आठ महीने पहले नर्सिंग होम्स को नियमित करने के प्रयास शुरू किए थे। अस्पताल संचालकों को बुलाया था। उन्हें बताया था कि संबंधित क्षेत्र की कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से कॉमर्शियल व रेसीडेंशियल रेट के अंतर की 25 फीसदी राशि शुल्क के तौर पर चुकाना होगी। यह एक बार देना होगी।

संचालक इसके लिए तैयार नहीं हुए। फीस को ज्यादा बताया। इसके बाद शुल्क आधा करने का प्रस्ताव कमिश्नर ने शासन को भेज दिया। कुछ दिन बाद वहां से यह प्रस्ताव लौटा दिया गया। नगर निगम को ही यह तय करने के लिए कहा गया। अब करीब एक महीना गुजर चुका है पर फीस फाइनल नहीं हो पाई है।

वैध होने के लिए यह जरूरी

- अस्पताल का निर्माण न्यूनतम 4000 वर्गफीट और सामने न्यूनतम 12 मीटर सड़क जरूरी होगी।
- साथ ही अस्पताल प्रबंधन को पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। यदि उनके पास पार्किंग नहीं है तो नगर निगम की पार्किंग में पैसा देना होगा। यह रकम कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से होगी।
- रिहायशी क्षेत्र में अस्पताल चलाने के लिए एकमुश्त के साथ सालाना अधिभोग शुल्क भी देना होगा।

Badri Gautam

सीबीएसई ने जारी किया 9वीं से 12वीं का अपडेट सिलेबस

● लेक सिटी रिपोर्टर ●

सीबीएसई ने एकेडमिक ईयर 2021-2022 के लिए नया सिलेबस जारी किया है। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbseacaçemic.nic.in के जरिए अपना नया सिलेबस चेक कर सकते हैं। नए सिलेबस के मुताबिक सीबीएसई ने एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए सिलेबस में कोई कमी नहीं की है। यानी कि स्टूडेंट्स को पूरे 100 प्रतिशत सिलेबस की पढ़ाई करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि 4 मई से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले कोरोना संक्रमित स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम से पूरी तरह छूट दी जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स अप्रैल या थ्योरी परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल हो सकेंगे।

एजुकेशन अपडेट

Badri Gautam

एंकर स्टोरी

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम विवादों से उबरा

वर्चुअल मोड में अब 6 अप्रैल को होगा कार्यक्रम, 23 का होगा सम्मान

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग का हर साल विवादों में घिरा रहने वाले वाला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह पिछले साल स्थगित होने के अब छह माह बाद 6 अप्रैल को वर्चुअल मोड में किया जाएगा। अब इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से चयनित किए गए 25 शिक्षकों में से 23 शिक्षकों को ही सम्मानित किया जाएगा। विवादों के चलते दो शिक्षकों का नाम सूची से काट दिया गया है। विभाग ने कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के साथ ही चयनित शिक्षकों की नई सूची भी जारी कर दी है।

दरअसल, राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2020 के लिए विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले प्रदेश के 25 शिक्षकों का चयन किया था। इसकी सूची बीते साल 27 अगस्त 2020 को जारी की गई थी। शिक्षकों का सम्मान 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर मिलना था। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के निधन के कारण सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में चयनित शिक्षक नई तारीख ऐलान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही यह कार्यक्रम विवादों से घिर गया। जारी सूची में से कुछ शिक्षकों के नाम और चयन प्रक्रिया को लेकर शिक्षक संगठनों ने विरोध किया और शिकायतें विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंची। जिसके बाद सूची को स्थगित करते हुए राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार ने मामले में एक जांच समिति बना दी।

जिसकी रिपोर्ट के बाद अब विभाग ने 6 माह बाद 23 शिक्षकों की नई सूची जारी करते हुए 6 अप्रेल 2021 को शिक्षक सम्मान कार्यक्रम वर्चुअल मोड में आयोजित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से होगा कार्यक्रम

लोक शिक्षण संचालनालय ने संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 कार्यक्रम का आयोजन समारोह के रूप में न किया जा कार इसे एनआईसी की वीसी के माध्यम से 6 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से 4.30 बजे तक किया जाएगा। इस वीसी की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी। जिसमें प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा भी मौजूद रहेंगी। वीसी में ही राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित शिक्षक संजय कुमार जैन, शास. प्राथमिक शाला डूंडा, जिला टीकमगढ़ और मोहम्मद शाहिद अंसारी, शास. हायर सेकेंडरी विद्यालय सिरसाडोह, जिला छिंदवाड़ा को वल्लभ भवन भोपाल स्थित एनआईसी के वीसी कक्ष में सम्मानित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 6 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर स्थित एनआईसी के वीसी कक्ष में जिला कलेक्टर द्वारा सूची में शामिल शिक्षकों और प्राचार्यों को सम्मानित किया जाएगा।

इन्हें भी मिलेगा सम्मान

राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2020 से सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची के साथ ही विभाग ने शिक्षक दिवस 2020 के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाईन राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी 2020 के 2 विजेता शिक्षक, 90 प्रतिशत से अधिक रिजल्ट देने वाले स्कूलों के 83 प्राचार्यों की सूची भी जारी की है। जिन्हे सम्मानित किया जाएगा।

इनका नाम हटाया गया

चयनित सूची में राजधानी से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आनंद नगर के व्याख्याता राधाकृष्णन केसी और सीधी जिले की अजीता द्विवेदी के नाम विरोध हुआ था। इस मामले को लेकर राज्यपाल व मंत्री से शिकायत की गई। जिसके बाद मामले में जांच कराई गई और इन दोनो के नाम को हटाया गया है।

शिक्षक सम्मान समारोह के लिए 22 शिक्षकों की नई सूची जारी कर दी गई है। यह सम्मान समारोह कोरोना संक्रमण के चलते वर्चुअल मोड पर आयोजित किया जाएगा। जिन नामों पर विवाद था, उन्हें जांच के बाद हटा दिया गया है। इन विवादित नामों को जोड़ने वालों की जांच कराकर उन पर कारर्वाई तय की जाएगी।

इंदरसिंह परमार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा

Badri Gautam

खुशखबरी पिछले साल मार्च में 23.52 थी दर, अब धीरे-धीरे होने लगी है रिकवरी, बढ़ रहीं नौकरियां

बेरोजगारी की दर गिरकर 6.52 प्रतिशत पर आई

नई दिल्ली, जेएनएन। कोविड के कहर वाले वित्त वर्ष 2020-21 ने जाते-जाते रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी खबर दी है। पिछले महीने देश में बेरोजगारी का स्तर गिरकर 6.52 प्रतिशत पर आ गया। यानी 10,000 वर्कर में 652 बेरोजगार थे। फरवरी में बेरोजगारी का आंकड़ा 6.90 प्रतिशत था। ये आंकड़े बिजनेस और इकोनॉमिक रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने जारी किए हैं। हालांकि, उसके आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में बेरोजगारी में कमी के बीच एक निराश करने वाली खबर भी है। शहरों में बेरोजगारी का लेवल 7.24 प्रतिशत रहा। यानी 10,000 वर्कर में 724 बेरोजगार थे। फरवरी में यह आंकड़ा 6.99 प्रतिशत यानी 10,000 में 699 का था। इसका मतलब यह है कि शहरी क्षेत्रों में रिकवरी की रफ्तार धीमी है। बेरोजगारी साल के पहले महीने में भी घटी थी। जनवरी में शहरों में बेरोजगारी 8.08 प्रतिशत के लेवल पर थी जो दिसंबर के 8.84 प्रतिशत से खासी कम रही थी। सीएमआईई ने कहा है कि यह सही है कि देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अगर व्यापक पैमाने पर लॉकडाउन नहीं लगाया, तो आगे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। विज्ञान से हमें वायरस से बचाव का टीका मिला है। मनमाने तरीके से लॉकडाउन करने के बजाय फिजिकल डिस्टेंस का अनुशासन बनाए रखते हुए कारगर तरीके से टीकाकरण करते रहना बेहतर होगा। एजेंसी ने कहा है कि सरकार को भी भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि वह व्यापक लॉकडाउन नहीं लगाएगी। वह ऐसा कुछ नहीं करेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियां कमजोर पड़ें।

Badri Gautam

पिछले साल खराब थी स्थिति

सीएमआईई ने कहा है कि लॉकडाउन होने से रोजी-रोटी छिनने का खतरा बढ़ जाता है। पिछले साल जब कोविड की रोकथाम के लिए पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था, तब अप्रैल में बेरोजगारी का लेवल 23.52 प्रतिशत था। यानी 10,000 वर्कर में 2,352 लोग बेरोजगार हो गए थे। मई में हालात थोड़े बेहतर हुए थे, जिससे बेरोजगारी का आंकड़ा 21.73 प्रतिशत पर आया था। इस हिसाब से उस महीने 10,000 वर्कर में 2,173 बेरोजगार थे। एजेंसी ने कहा है कि पिछले साल जैसी स्थिति अब नहीं बनेगी।

टोटल लॉकडाउन का होगा बुरा असर

सीएमआईई ने कहा है कि देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं, लेकिन उम्मीद है कि सरकार टोटल लॉकडाउन से बचेगी, क्योंकि उसे भी देश की अर्थव्यवस्था की चिंता है। एजेंसी ने सुझाव दिया है कि टोटल लॉकडाउन लगना भी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिससे देश की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो जाएं। उसने सुझाव दिया है कि कोरोना की बढ़त को रोकने के लिए केवल आंशिक लॉकडाउन पर्याप्त रहेगा। नाइट कर्फ्यू और भीड़ को एक जगह एकत्रित भी नहीं होने देना चाहिए। लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। वे मास्क पहनें और कोरोना के नियमों का पालन करें। एजेंसी ने कहा है कि अगर टोटल लॉकडाउन होता है, तो इससे फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा।

चहेतों को सेट कराने नियमों की अनदेखी का आरोप

ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर फंस सकता है पेंच

रादुविवि भर्ती का रोस्टर जारी होते ही विवादों में घिरा

जबलपुर। सालों के इंतेजार के बाद किसी तरह रानी दुर्गावति विश्वविद्यालय में भर्ती का रास्ता खुला, लेकिन प्रारंभ में ही संभावित भर्ती प्रक्रिया तकनीकी पेंचों में उलझती नजर आ रही है. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (आरडीयू) प्रशासन द्वारा कमेटी ने आखिरकार लंबी कवायद के बाद शिक्षकों की रिक्त पदों में भर्ती को ध्यान में रखते हुए मॉडल रोस्टर को जारी कर दिया। प्रोफेसर पीके सिंघल के अध्यक्षता वाली कमेटी ने करीब 13 पन्नों का मॉडल रोस्टर जारी किया है। जिसमें अनु.जाति को 16 फीसदी,अनु. जनजाति को 20 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 फीसदी आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। कमेटी ने विश्वविद्यालय को एक ईकाई मानते हुए मॉडल रोस्टर तैयार किया है। लेकिन विशेषज्ञ उक्त रोस्टर में कई तकनीकी गलतियां निकाल रहे हैं। वहीं आरोप यह भी लग रहे हैं की पूरा रोस्टर इस हिसाब से तैयार किया गया है। रादुविवि के प्रोफेसरों और कर्मचारियों के बच्चों को सेट कराया जा सके। बताया जाता है कि करीब 23 ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके लिए रोस्टर को ऐसा डिजाइन करना था कि वे अपने योग्यता के अनुसार उक्त संबंधित विभाग में सेट हो जाएं।

Badri Gautam

एमपी हाईकोर्ट में याचिका भी दायर है

जानकारों का कहना है कि आरडीयू प्रशासन ने ओबीसी वर्ग के लिए 14 फीसदी आरक्षण का निधारण किया है। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने जो मॉडल रोस्टर विश्वविद्यालय को भेजा था उसमें ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ दिए जाने की बात कहीं गई थी। इस मामले को लेकर एमपी हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है जिसमें सरकार द्वारा जबाव प्रस्तुत किया जाना है। लेकिन अभी तक उच्च शिक्षा विभाग ने न तो 27 फीसदी आरक्षण को वापस 14 फीसदी किए जाने को लेकर कोई आदेश जारी किया है और न ही कोर्ट ने इस संबंध में को आदेश दिया है। लेकिन इसके बाद भी विश्वविद्यालय की आरक्षण कमेटी ने किस आधार पर ओबीसी वर्ग का आरक्षण घटा दिया इसको लेकर सवाल उठना तय है।

ईडब्लयूएस का जिक्र तक नहीं

आरडीयू के मॉडल रोस्टर में ईडब्लयूएस वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने ईडब्लयूएस पर्ग को भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ देने को लेकर आदेश पूर्व में जारी किए हुए हैं। बात साफ है कि ईडब्लयूएस आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट जाएगा।

10वीं-12वीं का फैसला 15 अप्रैल के बाद होगा

जबलपुर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सात शहरों में 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज तो बंद कर ही दिए गए हैं इतना ही नहीं इन शहरों में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अब 9वीं-11वीं की परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न पर कराने पर विचार कर रहा है। वहीं 10वीं व 12वीं की 30 अप्रैल से होने वाली परीक्षाओं पर भी संकट मंडरा रहा है। इन दोनों बोर्ड परीक्षाओं पर 15 अप्रैल तक फैसला लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनरल प्रमोशन किसी क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा। पैटर्न कोई भी हो लेकिन मूल्यांकन अवश्य किया जाएगा। 9वीं-11वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं 12 अप्रैल से शुरू होना थी, विभाग द्वारा दोनों ही कक्षाओं के टाइम टेबल भी जारी कर दिए गए थे। इसी तरह दो महीने पहले से 10वीं के 30 अप्रैल व 12वीं के 1 मई से पेपर शुरू करने के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया था। अब चूंकि कोरोना के प्रकरण हर रोज बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज 15 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। इसके चलते उक्त परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों ने 9वीं व 11 की ऑनलाइन परीक्षाएं करा ली हैं, सरकारी स्कूलों की परीक्षाओं पर निर्णय होना है।

ओपन बुक पैटर्न पर हो सकती हैं 9वीं-11वीं की परीक्षा

Baori Gaurav

परीक्षार्थियों की मदद के लिए सीबीएसई ने लॉन्च किया पोर्टल

नई दिल्ली, जेएनएन। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की 4 मई से शुरू होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्र-छात्राओं के लिए 'ई परीक्षा' पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से मई में बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल सकेगा। इस पोर्टल में परीक्षा की डेट शीट, प्रैक्टिकल एग्जाम, एग्जाम सेंटर और शिकायत निवारण से संबंधित सहित अन्य सभी जानकारियां देने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म की तरह इसे लॉन्च किया गया है। 10वीं और 12वीं के छात्र सीबीएसई ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल पर जाकर बोर्ड परीक्षा में अपने स्कूल के रोल नंबर का उपयोग करके यूजरआईडी और पासवर्ड एंटर करके इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। ई परीक्षा पोर्टल में विभिन्न सेक्शन हैं, जैसे परीक्षा या प्रैक्टिकल परीक्षा केंद्र में बदलाव। कक्षा 12 के छात्रों के लिए इंटरनल मार्क्स अपलोड करना, कक्षा 10 के छात्रों के लिए आंतरिक ग्रेड या प्रैक्टिकल डेटा अपलोड करने के साथ ही परीक्षा में ■ शेष पृष्ठ 9 पर

Badri Gautam

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा

लड़कियों के लिए सेनेटरी नैपकिन व टॉयलेट भी शिक्षा के अधिकार दायरे में लाएं

नई दिल्ली, जेएनएन। छह से चौदह वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार लड़कों और लड़कियों को समान रूप से मिला हुआ है, लेकिन कई बार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टायलेट और सेनेटरी नैपकिन आदि न होने से उनके लिए इस अधिकार को सही मायने में प्राप्त कर पाना मुश्किल होता है। इस बात को कर्नाटक हाईकोर्ट ने समझा है और इन मूलभूत सुविधाओं को शिक्षा के अधिकार के दायरे में लाने की बात कही है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह बात सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अन्य सुविधाओं के साथ मुफ्त में सेनेटरी नैपकिन बांटने की कर्नाटक सरकार की शुचि योजना को कड़ाई से लागू करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।

Bauri Gautam

सरकारी कार्यालयों में कोरोना ने जबर्दस्त तरीके से पैर पसारे

लोक निर्माण विभाग में एक कर्मचारी ने कोरोना से जंग हारी

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

सरकारी कार्यालयों में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। लगातार इस बीमारी की चपेट में आ रहे लोक निर्माण विभाग में एक कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई। मंत्रालय सहित अन्य विभागीय कार्यों में जबरदस्त तरीके से महामारी पैर पसार रही है। लोक निर्माण विभाग में जबरदस्त तरीके से कोरोना बढ़ रहा है। यहां पर कार्यालय प्रमुख अभियंता राजधानी परिक्षेत्र भोपाल में पदस्थ एक लिपिक कर्मचारी की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दर्जन भर से अधिक इंजीनियर एवं लिपिक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय में कोरोना पीड़ितों की संख्या एक दर्जन से ऊपर पहुंच चुकी है। महिला बाल विकास में भी कोरोना बढ़ने के कारण बाहरी लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र में हर दिन एक न एक कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। यहां पर भी बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आधा दर्जन अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं।

यहां पर जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश कार्यालय में ना किया जाए। बाबुओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह बाहर से आने वाली किसी व्यक्ति से ना मिले। इधर सरकारी स्कूलों में भी कोरोना जमकर काहे बरसा रहा है। शासकीय कमला नेहरू नवीन कन्या सरदार पटेल करो नूतन सुभाष जैसी स्कूलों में शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं।

सभी कार्यालयों में लगवाया जाए टीका : सलीम खान

मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष सलीम खान का कहना है कि सरकार को समस्त शासकीय कार्यालयों में कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाना चाहिए। इसकी शुरुआत जल्द होना चाहिए। क्योंकि प्रतिदिन काम करते कर्मचारी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इसमें जहां आर्थिक हानि हो रही है तो जान-माल की क्षति भी लगातार हो रही है। सरकार को शासकीय दफ्तरों में कोरोना रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।

कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी : वर्मा

तृतीय वर्ग संघ के प्रांतीय सचिव संतोष वर्मा का कहना है कि समस्त कार्यालयों में भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। हर दिन देखने को यह भी मिल रहा है कि अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी मास्कनहीं लगाते हैं। नियम बनाया जाए कि जो अधिकारी या कर्मचारी महासंघ लगाएं, उन पर दंड निर्धारित हो। जब यह कड़ाई रहेगी तभी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है।

आक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत : सिविल सर्जन डॉ श्रीवास्तव

भोपाल। जयप्रकाश अस्पताल के अधीक्षक एवं सिविल सर्जन डॉ राकेश श्रीवास्तव ने आक्सीजन की कमी से 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत सम्बन्धी खबरों पर स्पष्टीकरण और वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए इस तरह की खबरों को निराधार बताया है। डॉ श्रीवास्तव ने बताया कि वस्तुस्थिति यह है कि जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल में सेंटर आक्सीजन सप्लाई प्रत्येक बेड पर उपलब्ध कराई गई है और आक्सीजन हेतु एक सेंट्रल स्टेशन भी बनाया गया है। जिसके माध्यम से प्रत्येक बेड पर आक्सीजन सप्लाई की जाती है । जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल में 31 मार्च की स्थिति में कुल 64 आक्सीजन सिलेंडर भरे हुये थे जो आक्सीजन प्लांट पर ही रखे हुये है । सिलेडर की कमी नहीं थी । उन्होंने कहा कि जिन दोनों मरीजों की मृत्यु हुई है वे बेहद गम्भीर स्थिति में अस्पताल लाये गए थे । श्रीमती रामरती देवी उम्र 50 वर्ष निवासी कल्याण नगर 28 मार्च को रात्रि 9. 54 मिनट पर जय प्रकाश चिकित्सालय के कोविड .19 आईसीयू में बुखार सांस लेने में तकलीफ के कारण भर्ती हुईं । मरीज को उक्त तकलीफभर्ती होने से पूर्व 4 दिन से निरंतर थी साथ ही वे मधुमेह रोग से पीड़ित थी । दूसरे प्रकरण के बारे में डॉ श्रीवास्तव ने बताया कि सीबी मेश्राम उम्र 69 वर्ष 31 मार्च को शाम 6. 34 मिनट पर गंभीर अवस्था में ड्यूटी डॉक्टर द्वारा रैपिड टेस्ट नेगेटिव होने के कारण आईसीयू में भर्ती किया गया। भर्ती के समय पेशेंट का आक्सीजन कन्संट्रेशन 70 प्रतिशत था।

Badri Gautam

बीयू के 26 विभागों में 40 प्रोफेसर, एक पर 3 विभागों की जिम्मेदारी, पढ़ाई हो रही प्रभावित

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9893231237

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) में नियमित प्रोफेसरों की कमी के कारण सभी विभागों की शैक्षणिक व्यवस्था बिगड़ रही है।

बीयू के 26 विभागों में केवल 40 नियमित प्रोफेसर हैं। स्थिति यह है कि एक-एक प्रोफेसर को तीन-तीन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कारण प्रोफेसर ऑनलाइन क्लास भी सुचारु नहीं ले पा रहे हैं। रिसर्च वर्क भी प्रभावित हो रहा है। जानकारी के अनुसार, बीयू में प्रोफेसरों के कुल 108 पद हैं। इनमें से 68 पद लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं। वर्ष 2014 में तत्कालीन कुलपति एमडी तिवारी ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की थी, लेकिन यह नियुक्ति विवादों में है।

कुछ प्रमुख प्रोफेसर और उन्हें दिए गए विभाग

- **विनय श्रीवास्तव:** डीन, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, स्टेम सेल, एग्जाम कंट्रोलर, गेस्ट हाउस प्रभारी, क्रय समिति अध्यक्ष।
- **रुचि घोष:** डीन, सोशल साइंस, सोसलॉजी और महिला अध्ययन।
- **पवन मिश्रा:** डीएसडब्ल्यू, कॉमर्स हेड और डीन।
- **डीसी गुप्ता:** नैक समन्वयक और भूगर्भ शास्त्र एचओडी
- **विपिन व्यास:** एक्वाकल्चर, जूलॉजी, निम्नोलॉजी और पर्यावरण विभाग।
- **अनिल प्रकाश:** जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी।
- **रागनी गोथरवाल:** बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी।
- **नीरज गौर:** इलेक्ट्रॉनिक और बीयूआईटी।

बरकतउल्ला में 26 विभाग संचालित हो रहे हैं, जबकि केवल 40 प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हैं। ऐसे में एक प्रोफेसर पर दो से तीन विभागों की जिम्मेदारी आना तय है। प्रोफेसरों की नियुक्तियां होने से काफी हद तक समस्याएं हल हो सकती हैं।

–डॉ. एचएस त्रिपाठी, रजिस्ट्रार, बीयू

Badri Gautam

कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम बना हरासमेंट का जरिया, महिलाओं ने आयोग में की शिकायत, कहा-

बॉस कभी भी करते हैं वीडियो कॉल, भाषा का भी नहीं रखते ध्यान

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9827229058

बीते साल लॉकडाउन के चलते शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और तनाव का कारण भी बना है। कुछ सेक्टर में यह कल्चर अब भी जारी है और महिलाएं हरासमेंट की दिक्कतों से गुजर रही हैं।

महिला आयोग की सदस्य संगीता शर्मा इस बात की पुष्टि करती हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई-अगस्त में उनके और राज्य महिला आयोग के अन्य सदस्यों के पास ऐसी अनेक महिलाओं के कॉल और ई-मेल पहुंचे। हालांकि, 90 प्रतिशत मामलों में महिलाएं आधिकारिक शिकायत करने की बजाए परामर्श लेना चाहती

हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह बस उनकी समस्या हल हो जाए। महिला आयोग की सदस्य संगीता शर्मा के मुताबिक आयोग में बीते साल अप्रैल से अब तक आधिकारिक रूप से दर्ज ऐसी शिकायतें 3 प्रतिशत हैं। वहीं अनआधिकारिक रूप से इसी समयावधि में हमारे पास प्रदेशभर से 287 शिकायतें पहुंची हैं। इस आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि असली में संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है।

इस तरह की पहुंचीं शिकायतें

केस:01 आयोग की सदस्य को फोन कर शिक्षा संस्थान में कार्यरत महिला ने बताया कि बॉस काम के बहाने से किसी भी समय उसे वीडियो कॉल करते हैं और कॉल पर अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, जो उसे असहज कर जाता है।

केस:02 प्रायवेट लोन सेक्टर से जुड़ी कंपनी में कार्यरत महिला ने एडवोकेट से पूछा कि बॉस ऑनलाइन मीटिंग के वक्त गर्मी होने का बहाना बनाकर कम कपड़ों में बैठते हैं। बैठने की पॉजिशन भी गंदी होती है। क्या यह सेक्युअल हरासमेंट है।

कंफ्यूज हैं महिलाएं

मामले बताते हैं कि इस तरह के व्यवहार से महिलाएं बेहद असमंजस में हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि यौन उत्पीड़न हो रहा है या नहीं, या इससे कैसे निपटा जाए। इस दौरान महिलाओं से दोस्त बनने की रिक्वेस्ट की जाती है तो कभी पर्सनल बातें जिनमें पहनावे और खूबसूरती जैसे विषय शामिल होते हैं, इन पर बात की जाती है। साथ ही सोशल मीडिया पर पीछा करने, अनजान व्यक्तियों द्वारा तस्वीरों पर टिप्पणी किए जाने, और अनावश्यक फ्रेंड रिक्वेस्ट और कॉल्स जैसी समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।

स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने से आ रही है समस्या

एडवोकेट और काउंसलर सरिता राजानी ने बताया कि कंपनियों की ओर से इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि घर से काम किस तरह होना चाहिए। कोविड काल में महिलाएं अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, इसलिए वे सुनिश्चित नहीं कर पाती कि उन्हें इस बारे में आवाज उठानी चाहिए अथवा नहीं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वर्क ने महिलाओं के लिए अधिक मानसिक तनाव उत्पन्न किया है। उनके पास लॉकडाउन और अनलॉक में औसतन हर रोज तीन शिकायतें पहुंच रही हैं और अब भी जारी हैं। उनकी समस्याओं को निदान की कोशिश की जा रही है।

Badri Gautam

शिक्षक भर्ती: दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 45-45 अभ्यर्थियों को बुलाया

भोपाल। सरकारी स्कूलों में खाली पड़े माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए दो साल पहले परीक्षा से चुने गए 20,670 युवाओं के दस्तावेजों का सत्यापन एक अप्रैल से शुरू हो गया है। राजधानी में पहले दिन डीईओ-जेडी कार्यालय में 10-10 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया था।

अब 3 अप्रैल को 45-45 अभ्यर्थियों को जेडी-डीईओ कार्यालय में बुलाया गया है। अप्रैल में 1, 3, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27 एवं 28 तारीख का दिन सत्यापन के लिए नियत किया गया है। विभाग ने 2018 में 5670 माध्यमिक और 15 हजार उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। फरवरी-2019 में परीक्षा हुई थी। कुछ महीनों बाद परिणाम भी घोषित कर दिया था। नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई और सितंबर में शुरू हुई थी। लेकिन शासन ने कोरोना संक्रमण बढ़ने का अंदेशा जताते हुए बीच में ही काउंसिलिंग स्थगित कर दी थी।

Badri Gautam

अब 25 की जगह 23 शिक्षकों का 6 को वर्चुअल होगा सम्मान

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893231237

शिक्षक दिवस पर आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम लगभग 6 माह बाद 6 अप्रैल को वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अब प्रदेशभर से चयनित किए गए 25 शिक्षकों में से 23 शिक्षकों को ही सम्मानित किया जाएगा।

दो शिक्षकों के नाम सूची से स्कूल शिक्षा विभाग ने हटा दिए हैं। विभाग ने चयनित शिक्षकों की नई सूची भी जारी कर दी है। दरअसल, राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2020 के लिए विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले प्रदेश के 25 शिक्षकों का चयन किया था। इसकी सूची भी 27 अगस्त 2020 को जारी कर दी गई थी। शिक्षकों को सम्मान 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर मिलना था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के निधन के कारण सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था।

इन्हे भी मिलेगा सम्मान : राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2020 से सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची के साथ ही विभाग ने शिक्षक दिवस 2020 के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी 2020 के 2 विजेता शिक्षक, 90 प्रतिशत से अधिक रिजल्ट देने वाले स्कूलों के 83 प्राचार्यों की सूची भी जारी की है। इन्हे भी 6 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा।

Badri Gautam

अध्यापक संवर्ग के 7वें वेतनमान का सही निर्धारण किया जाए

भोपाल| मप्र शिक्षक कांग्रेस ने अध्यापक संवर्ग के सातवें वेतनमान के निर्धारण में व्याप्त विसंगति को दूर करने की मांग की है। प्रांतीय प्रवक्ता सुभाष सक्सेना ने बताया कि अध्यापक संवर्ग का 7वें वेतनमान के निर्धारण में एचआरए राशि शामिल होगी। नियमित शिक्षक और अध्यापक संवर्ग का एरियर निर्धारण एक समान नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान में एचआरए नहीं मिल रहा था, जबकि नियमित शिक्षक संवर्ग को छठवें वेतनमान में एचआरए पहले से मिल रहा है। जिन संकुल केंद्रों ने एरियर में एचआरए नहीं जोड़ा है उन्हें सभी वेतनभत्तों के साथ एरियर का निर्धारण करना होगा। अध्यापक संवर्ग को जुलाई 2018 नए केडर में शामिल कर भत्तों का लाभ दिया गया।

Badri Gautam

बीयू... परीक्षार्थी के निवास के पास स्थित केंद्र पर जमा होंगी कॉपियां

यूजी की पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न पर होंगी

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

बरकतउल्ला विवि की यूजी पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न के आधार पर होंगी। इसमें आंतरिक मूल्यांकन के नंबर भी जुड़ेंगे। इसमें दो पेपर होंगे, जो 50-50 नंबर के रहेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इन परीक्षाओं के लिए मार्किंग का पैटर्न जारी कर दिया है। इसके तहत यह परीक्षाएं जून में होना प्रस्तावित है। इसके साथ यूजी अंतिम वर्ष और पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं पेन पेपर मोड पर भौतिक रूप से परीक्षा केंद्रों पर होंगी। बीयू सहित अन्य विवि अपनी वेबसाइट पर यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष के पेपर डाउनलोड करेंगे। परीक्षा परिणाम जुलाई में अनिवार्य रूप से घोषित करना होंगे। परीक्षार्थियों को ए4 साइज के पेपर की कॉपी बनाकर उत्तर लिखना होंगे। इसमें छात्र को रोल नंबर, नामांकन, कॉलेज का नाम सहित अन्य जानकारी भरना होगी। कॉपी परीक्षार्थी के निवास के पास स्थित केंद्र पर जमा होंगी। इसकी लिस्ट विवि जारी करेंगे।

मुख्य विषयों के दो प्रश्नपत्र - अधिकारियों ने बताया कि पहले व दूसरे वर्ष की परीक्षाओं में मुख्य विषयों के दो-दो पेपर होंगे। इनका योग 100 होगा। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. धीरेंद्र शुक्ला ने बताया कि सभी विवि को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। वे तैयारी कर टाइम टेबल घोषित करेंगे और तय समय पर परीक्षाएं आयोजित करेंगे।

आंतरिक मूल्यांकन के नंबर भी जुड़ेंगे

परीक्षा परिणाम यूजी प्रथम वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन और ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर घोषित किया गया जाएगा। इस वर्ष के प्राइवेट छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर घोषित होगा। इसी तरह स्नातक दूसरे वर्ष के लिए परीक्षा परिणाम ओपन बुक से प्राप्त प्राप्तांक और आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर 50 प्रतिशत और पिछले वर्ष के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत जोड़कर घोषित होगा। वहीं, प्राइवेट छात्रों के लिए ओपन बुक पैटर्न से आयोजित परीक्षा के 50 प्रतिशत और पिछले साल के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंक जोड़कर परिणाम घोषित होगा।

अलग से लगाएंगे कक्षाएं

कोर्स भी अब तक नहीं हुआ पूरा

इधर, देर से दाखिला लेने वाले छात्रों का कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। इनका 40 प्रतिशत से भी ज्यादा कोर्स बचा हुआ है। इस समय कॉलेजों में भी कक्षा नहीं लग रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। अलग से कक्षा लगाकर भी कोर्स पूरा करवाएंगे।

Badri Gautam

पीएफ संबंधी समस्या है तो 8305411688 नं. पर करें वाट्स एप

पीएफओ को 24 घंटे में कभी भी शिकायत करें, मिलेगा जवाब, कार्यालय में भी सुनवाई के लिए अलग व्यवस्था

इंदौर • डीबी स्टार

भविष्य निधि संगठन (पीएफओ) इंदौर रीजन के साढ़े पांच लाख हितग्राहियों की शिकायतों और उनके समाधान पर विशेष ध्यान देगा। शिकायती पोर्टल पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब वाट्स एप नंबर 8305411688 नंबर भी जारी कर दिया है। साथ ही भविष्य निधि कार्यालय में शिकायतें लेकर आने वालों को विशेष तौर पर सुना जाएगा।

पीएफओ के इंदौर रीजन में करीब साढ़े पांच लाख लोग ऐसे हैं, जिनका पीएफ अंशदान नियमित तौर पर जमा होता है। वहीं, लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नौकरी तो छोड़ दी है लेकिन अब तक पीएफ खाते में जमा राशि किन्हीं कारणों से नहीं निकाली है। इन सभी लोगों को नौकरी के दौरान वेतन से रुपए काटे जाने और नौकरी छोड़ने के बाद खाते से रुपए निकालने को लेकर कई तरह की समस्याएं आती हैं। हजारों लोग इन समस्याओं के लिए पीएफ कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं मिल पाता। इस स्थिति को सुधारने के लिए भविष्य निधि आयुक्त ने निर्णय लिया है कि 2021 में सिर्फ लोगों की समस्याओं और उनके समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालांकि शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था पहले से ही चल रही है, लेकिन इसके लिए अब नंबर भी जारी किया गया है। यह बिजनेस वाट्स एप नंबर है, जिस पर आप कभी भी अपनी शिकायत या सवाल भेज सकते हैं। एक कर्मचारी को इस नंबर पर जवाब देने की जिम्मेदारी दी गई है। भविष्य निधि कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से व्यवस्था की है। इसके लिए अलग-अलग लोगों की जिम्मेदारी तय की है। वहीं, आयुक्त अमरदीप मिश्र ने बताया कि वे भी रोज कम से कम एक व्यक्ति से मिलकर उसकी समस्या पर बात और समाधान करेंगे।

Badri Gautam

एजुकेशन अपडेट

सीए (मई) परीक्षा के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू

सिटी रिपोर्टर . भोपाल

आईसीएआई ने सीए मई परीक्षा 2021 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट icaiexam.icai.org के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 13 अप्रैल तय की गई है।

21 मई से शुरू होगी परीक्षा : आईसीएआई ने सीए मई परीक्षाओं के लिए 19 फरवरी, 2021 का शेड्यूल जारी किया था। जारी शेड्यूल के मुताबिक फाइनल और इंटरमीडिएट कोर्स की परीक्षा क्रमशः 21 और 22 मई, से शुरू होगी। वहीं, फाइनल कोर्स (ओल्ड और न्यू स्कीम) ग्रुप- 1 की परीक्षा 21, 23, 25 और 28 मई को और ग्रुप 2 परीक्षा 30 मई, 1, 3 और 5 जून को आयोजित होगी।

तीसरी से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए 100 से ज्यादा कॉमिक्स तैयार

न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूल के बच्चों की बेहतर शिक्षा व उनकी पढ़ाई आसान करने की ओर कदम उठाया गया है। इसमें तीसरी से लेकर 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 100 से अधिक कॉमिक तैयार की हैं। इन्हें देशभर से सीबीएसई स्कूल की करीब 1000 टीचर्स ने बनाया व क्यूरेट एनसीईआरटी ने किया है। यह कॉमिक बुक्स 16 विषयों पर बनाई गई हैं। इनको एनसीईआरटी करिकुलम के आधार पर तैयार किया है। सीबीएसई के अनुसार ये कॉमिक्स को छोटे- छोटे टॉपिक्स में बांटा गया है।

Badri Gautam

खेलो इंडिया एप से होगा स्टूडेंट्स का असेसमेंट

स्कूली स्टूडेंट्स में खेल कूद और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ फिट इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की है। कार्यक्रम से हर स्कूल को जोड़ने के लिए खेलो इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से 3 से 18 साल तक के स्टूडेंट्स जुड़ सकते है। जिसके बाद उनका असेसमेंट होगा।

अतिक्रमण • एसडीएम की लापरवाही से हुए बेजा कब्जे, कहीं दुकान तो कहीं बने मकान

भोपाल संभाग के 6 से ज्यादा एक्सीलेंस समेत कई सरकारी स्कूलों की जमीन पर हुए कब्जे

इछावर और बुदनी ब्लॉक के स्कूलों की जमीन नगर पालिका ने हथियाई

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 313 ब्लॉक एक्सीलेंस स्कूल शुरू किए गए थे। इन स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए क्षेत्रीय एसडीएम को चेयरमैन बनाया गया। लेकिन इनमें से कई स्कूलों में एसडीएम की लापरवाही के चलते उनकी जमीनों पर या तो अतिक्रमण हो गए या फिर सरकार के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए न कोई अनुमति ली जाती है और न ही विभाग को सूचित किया जाता है। यह हाल केवल भोपाल संभाग में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है। भोपाल संभाग में ही आधा दर्जन से अधिक एक्सीलेंस स्कूल की जमीनों पर बेजा कब्जे हो गए हैं। इनमें सबसे बुरी हालत सीहोर जिले की है। यहां इछावर और बुदनी ब्लॉक के एक्सीलेंस स्कूल की जमीनों पर नगर पालिका की नजर पड़ गई है। दोनों ही स्थान पर नगर पालिका अध्यक्ष जमीनों पर पार्क बनाने के लिए मटेरियल डाल चुके हैं। नसरुल्लागंज में तो स्थानीय पार्षदों के विरोध के बाद काम रुक गया, लेकिन यहां शासन ने स्कूल की करीब 20 एकड़ जमीन एक कॉलेज के लिए दे दी। बड़ी बात यह है कि उक्त जमीन स्कूल द्वारा शाला विकास निधि से करीब 40 साल पहले खरीदी गई थी। सीहोर जिले में दोराहा स्थित हायर सेकंडरी स्कूल की जमीन पर तहसील व पुलिस थाने में पदस्थ अफसरों के क्वार्टर बना दिए गए हैं। सीहोर से सटे जिले राजगढ़ के नरसिंहगढ़ ब्लॉक में दो स्कूलों की जमीन पर पूरा बाजार बना दिया गया है। गैरतगंज में जमीन पर आधा एकड़ से अधिक जमीन पर बंगले बना दिए हैं।

बाउंड्रीवॉल न होने से कई स्कूलों के परिसर में तन गईं झुग्गियां

Badri Gautam

यह है प्रदेश की स्थिति

313 स्कूलों में से सिर्फ 200 में ही बॉउंड्रीवाल

सभी एक्सीलेंस स्कूलों को कम से कम साढ़े चार एकड़ जमीन दी है। जमीन इमारत के अलावा है। जमीन बच्चों के लिए छात्रावास और खेल मैदान के लिए थी। कब्जे की मुख्य वजह यह है कि 313 स्कूलों में से करीब 200 स्कूलों की ही बाउंड्री वॉल बन पाई है।

रिपोर्ट मिलने के बाद शासन को लिखेंगे

संभाग के कुछ स्कूलों की जमीनों को लेकर विवाद है। हमने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि वे रिपोर्ट बनाकर दें। हम बाउंड्री वॉल बनाने के लिए भी शासन को लिखेंगे।

राजीव सिंह तोमर, संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल

कोरोना से इन परीक्षाओं पर भी संकट

अब स्कूल शिक्षा विभाग कर रहा बोर्ड परीक्षाओं पर विचार, मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में होगा फैसला

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भोपाल

प्रदेश में बेकाबू होता कोरोना संक्रमण इस बार फिर परीक्षाओं पर संकट बनकर खड़ा हो गया है। बढ़ते संक्रमण के चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी मंडल की ओर से इस प्रकार के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन विभागीय सूत्रों की माने तो आगामी 12 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में इसको लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। सीएम इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में मौजूदा हालातों पर कलेक्टरों से चर्चा करेंगे।

9वीं 11वीं और प्री बोर्ड पर भी असमंजस

प्रदेश के सात शहरों में नवमीं से बारहवीं तक की क्लास बंद करने से नवमीं-ग्यारहवीं की वार्षिक व दसवीं-बारहवीं की प्री-बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा नवमीं-ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षा व दसवीं.बारहवीं की प्री.बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से आयोजित की जाना है। अभी परीक्षा का कार्यक्रम ऑफलाइन तय किया गया है, लेकिन कोरोना संक्रण्मा को देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन परीक्षा कराने पर विचार शुरू कर दिया है। इसमें ओपन बुक एक्जाम पर भी विचार चल रहा है।

कर ली थी तैयारी

बता दें कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर कोरोना से बचाव के प्रबंध करने में निर्देश पहले ही जारी कर चुका है। इसके साथ ही बोर्ड तय कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। यदि 15 अप्रैल तक कोरोना संक्रमण कुछ कम हुआ या स्थिरता आई, तो परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग पहले ही परीक्षाएं इसी पद्धति से कराने का निर्णय ले चुका है।

BabriGautam

माशिमं की हेल्पलाइन पर पहले दिन आए 1400 कॉल्स

95 फीसदी छात्रों ने पूछा परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन

हरिभूमि, जबलपुर

माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। ऐसे में मंडल ने अपनी हेल्पलाइन 18002330175 के समय में 1 अप्रैल से बदलाव करते हुए इसे सभी दिवसों के लिए सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर दिया है। इस बदलाव का पहले दिन ही बड़ा असर देखने को मिला है। हेल्पलाइन पर जहां रोजाना 300 से 350 कॉल पहुंचते थे, वहीं पहले दिन हेल्पलाइन पर 1400 से अधिक विद्यार्थियों के कॉल पहुंचे हैं, जिसमें 95 फीसदी कॉल एकेडमिक हैं। इनमें एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम ऑफलाइन होगी अथवा ऑनलाइन होगी, एग्जाम में प्रश्न नए ब्लू प्रिंट या पुराने ब्लू प्रिंट से आएंगे, प्रश्न बैंक से कितने प्रश्न आएंगे इस प्रकार के सवाल विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए हैं। दरअसल, हेल्पलाइन पर पहले सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कार्यदिवसों में संपर्क किया जा सकता था, लेकिन अब इसके समय में मंडल ने 4 घंटे की बढ़ोतरी कर दी है।

मंडल की 18 साइकोलॉजिस्ट की टीम, काउंसलर और विशेषज्ञों की टीम विद्यार्थियों के सवालों का दे रही जवाब

तीन पालियों में काम करती है टीम

अभी हेल्पलाइन के लिए माशिमं ने 18 साइकोलॉजिस्ट की टीम, काउंसलर और विशेषज्ञों की टीम की व्यवस्था की है। जो विद्यार्थियों के सवालों का दे रही जवाब दे रही है और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रही है। यह टीम तीन पालियों में काम करती है। पहली पाली सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 12 से 4 बजे तक और तीसरी पाली शाम 4 बजे से 8 बजे तक काम करती है।

अभिभावक भी करते हैं कॉल

माशिमं की हेल्पलाइन परीक्षाओं के दौरान माशिमं की हेल्पलाइन पर कॉल्स की संख्या में तेजी से इजाफा होता है। इस दौरान अभिभावकों के कॉल की संख्या भी बढ़ जाती है। हेल्पलाइन पर आने वाले कॉल्स में 80 फीसदी कॉल विद्यार्थियों के होते हैं। 10 फीसदी शिक्षक और 10 फीसदी अभिभावकों के होते हैं। हेल्पलाइन पर आने वाले कॉल्स में 70 फीसदी कॉल एकेडमिक व कैरियर से संबंधित होते हैं। वहीं 20 फीसदी कॉल माशिमं के पोर्टल को लेकर आते हैं। इसके अलावा 10 फीसदी कॉल अन्य समस्याओं के लिए आते हैं।

हर समस्या का हमारे पास है समाधान

हमने विद्यार्थियों और हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले सभी व्यक्तियों की सहूलियत के लिहाज से बदलाव भी किए है। यहां विद्यार्थी खुलकर अपनी बात रख सकते है, उनकी हर समस्या का समाधान हमारे पास है।

डॉ. हेमंत शर्मा
प्रभारी, माशिमं हेल्पलाइन

बीते सालों में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक यह रही स्थिति

- 2018 में 1 लाख 6 हजार कॉल आए हैं।
- 2019 में 1 लाख 23 हजार कॉल आए हैं।
- 2020 में 2 लाख 35 हजार काल आए हैं।
- 2021 में जनवरी से लेकर 31 मार्च तक लगभग 17 हजार 856 कॉल आए हैं।

Badri Gautam

सीबीएसई की पहल

10वीं, 12वीं के छात्रों के लिए 'ई-परीक्षा' पोर्टल लांच

मई और जून में होंगी परीक्षाएं

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मई में होने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों की मदद के लिए 'ई-परीक्षा' नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस एक पोर्टल पर छात्रों के लिए परीक्षा की डेट शीट, प्रैक्टिकल एग्जाम, एग्जाम सेंटर और शिकायत निवारण से संबंधित हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी। छात्र सीबीएसई की ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल आधिकारिक वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं।

Badri Gautam

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम विवाद से उबरा, 23 नामों की नई सूची जारी

6 अप्रैल को वर्चुअल मोड में होगा शिक्षकों का सम्मान, भोपाल-सीधी का नाम हटाया

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

हर साल शिक्षक दिवस पर आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम अब लगभग 6 माह बाद विवादों के घेरे से उबर आया है। अब इस कार्यक्रम का 6 अप्रैल को वर्चुअल मोड में आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम में अब प्रदेशभर से चयनित किए गए 25 शिक्षकों में से 23 शिक्षकों को ही सम्मानित किया जाएगा। दो शिक्षकों के नाम सूची से स्कूल शिक्षा विभाग ने हटा दिए हैं। विभाग ने कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के साथ ही चयनित शिक्षकों की नई सूची भी जारी कर दी है।

राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2020 के लिए विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले प्रदेश के 25 शिक्षकों का चयन किया था। इसकी सूची भी 27 अगस्त 2020 को जारी कर दी गई थी। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, जिसके बाद यह कार्यक्रम विवादों से घिर गया। जारी सूची में से कुछ शिक्षकों के नाम और चयन प्रक्रिया को लेकर शिक्षक संगठन ने विरोध किया। अब विभाग ने 23 शिक्षकों की नई सूची के साथ 6 अप्रैल 2021 को शिक्षक सम्मान कार्यक्रम वर्चुअल मोड में आयोजित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

प्रदेशभर से चयनित किए गए 25 शिक्षकों में से 23 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा शिक्षक संगठन के विरोध के बाद विभाग ने दो शिक्षकों के नामों को सूची से हटा दिया

90% से ज्यादा रिजल्ट देने वाले प्राचार्य को पुरस्कार

राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2020 से सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सूची के साथ ही विभाग ने शिक्षक दिवस 2020 के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी 2020 के 2 विजेता शिक्षक, 90 प्रतिशत से अधिक रिजल्ट देने वाले स्कूलों के 83 प्राचार्यों की सूची भी जारी की है। जिन्हें सम्मानित किया जाएगा।

शिक्षक केसी को लेकर थी आपत्ति

पहले जारी की गई सूची में भोपाल के राधाकृष्णन केसी और रीवा के नीरज कुमार पांडेय के नाम पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। वहीं सीधी की टीचर अजीता द्विवेदी के नाम पर स्थानीय पर सतीश पांडेय द्वारा विधायक से शिकायत कर आपत्ति उठाई गई थी। इसको लेकर विभाग द्वारा कमेटी बनाकर जांच कराई गई। जांच के बाद नई सूची से व्याख्याता राधाकृष्णन केसी और सीधी जिले की टीचर अजीता द्विवेदी का नाम हटाया गया है।

जांच के बाद नाम हटाया

शिक्षक सम्मान समारोह कोरोना संक्रमण के चलते इस बार वर्चुअल मोड पर आयोजित किया जाएगा। जिन नामों पर विवाद था, उन्हें जांच के बाद हटा दिया गया है। विवादित नामों को जोड़ने वालों की जांच कराकर उन पर कार्रवाई तय की जाएगी। शिक्षक सम्मान समारोह के लिए 23 शिक्षकों की नई सूची जारी कर दी गई है।

इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा

स्कूल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से होगा कार्यक्रम

लोक शिक्षण संचालनालय ने संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 कार्यक्रम का आयोजन समारोह के रूप में न किया जा कार इसे एनआईसी की वीसी के माध्यम से 6 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक किया जाएगा। इस वीसी की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी। जिसमें प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा भी मौजूद रहेंगी। वीसी में ही राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित शिक्षक संजय कुमार जैन, शास. प्राथमिक शाला डूंडा, जिला टीकमगढ़ और मोहम्मद शाहिद अंसारी, शास. हायर सेकंडरी विद्यालय सिरसाडोह, जिला छिंदवाड़ा को वल्लभ भवन भोपाल स्थित एनआईसी के वीसी कक्ष में सम्मानित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 6 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर स्थित एनआईसी के वीसी कक्ष में जिला कलेक्टर द्वारा सूची में शामिल शिक्षकों और प्राचार्यों को सम्मानित किया जाएगा।

Badri Gautam

यूजी-पीजी फाइनल की ऑफलाइन परीक्षाओं का टाइम टेबल अगले सप्ताह

परीक्षाएं मई की शुरुआत में कराने की तैयारी

भास्कर संवाददाता | इंदौर

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल सेमेस्टर की ऑफलाइन परीक्षाओं का टाइम टेबल अगले सप्ताह जारी होगा। यूनिवर्सिटी मई के पहले सप्ताह में इनकी परीक्षा कराने की तैयारी में है। यदि कोरोना संक्रमण के हालात नहीं बदले तो यूनिवर्सिटी इसी टाइम टेबल को मई के अंतिम सप्ताह में लागू कर देगी। परीक्षा नियंत्रक डॉ. आशुतोष तिवारी ने बताया परिस्थिति के अनुसार परीक्षा का शेड्यूल लागू करेंगे। फिलहाल मई के पहले सप्ताह के अनुसार प्लान कर रहे हैं। दरअसल बीकॉम, बीए और बीएससी फाइनल ईयर तथा एमकॉम, एमए और एमएससी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं मई में ऑफलाइन होना हैं। यूनिवर्सिटी उसी के लिए यह टाइम टेबल जारी करेगी। पहले 15 मई के आसपास परीक्षा कराने का विचार था।

ठीक एक माह बाद ओपन बुक एग्जाम

यूनिवर्सिटी अगर मई के पहले सप्ताह में ऑफलाइन परीक्षा करवाती है तो फर्स्ट और सेकंड ईयर की ओपन बुक परीक्षा जून के पहले सप्ताह में होगी। वहीं पीजी दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी इसी के साथ ओपन बुक पद्धति से होगी।

Badri Gautam

एक्सीलेंस कॉलेज में डायरेक्टर नियुक्ति का मामला

एक दर्जन प्राचार्यों ने किए आवेदन, तीन का इंटरव्यू,लेकिन सभी डिसक्वालिफाई

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

प्रदेश के एकमात्र एक्सीलेंस कॉलेज में डायरेक्टर पद के लिए आए एक दर्जन प्राचार्यों के आवेदन में से तीन का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया था, लेकिन तीनों डायरेक्टर बनने के लिए डिसक्वालिफाई हो गए हैं। ऐसे में अब विभाग फिर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने की बात कह रहा है। बता दें कि एक्सीलेंस कॉलेज में डायरेक्टर की नियुक्ति विश्वविद्यालयों के कुलपति की तर्ज पर की जाना है।

मामले में अब उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन का कहना है कि एक्सीलेंस कॉलेज में सरकार ने पूर्णकालिक व योग्य डायरेक्टर की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। अभी काफी कम संख्या में प्राचार्यों के आवेदन आए थे, इसलिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अब नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी

एक्सीलेंस कॉलेज में अभी तक विभाग द्वारा कॉलेज के किसी प्रोफेसर या अधिकारी को प्राचार्य का प्रभार दे दिया जाता था। इसमें उनकी योग्यता नहीं देख जाती थी, लेकिन डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए विभाग ने अभी जो योग्यता तय की है, उसमें आवेदक का किसी सरकारी कॉलेज में रेगुलर कॉलेज में प्राचार्य होना अनिवार्य है।

तीन नामों का पैनल

कमेटी द्वारा तीन नामों का पैनल भेजी गई। इसमें स्टेट लॉ कॉलेज की प्राचार्य सुधा वैसा, भेल कॉलेज के प्राचार्य मथुरा प्रसाद और छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज के प्राचार्य के इंटरव्यू भी लिए गए हैं। लेकिन तीनों प्राचार्य डिसक्वालिफाई हो गए।

एसो. प्रोफेसर बनेंगे डायरेक्टर!

एक्सीलेंस में डायरेक्टर के पद के लिए एक नाम चर्चाओं में चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि अब मंत्रालय में पदस्थ अनिल कुमार पाठक की नियुक्ति की तैयारी है। जबकि नियुक्ति में प्राचार्य ही भाग ले सकते हैं और पाठक एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

Badri Gautam

सीबीएसई नए शैक्षिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम नहीं घटाएगा

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षिक वर्ष 2021-22 में नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में कमी नहीं करने का फैसला किया है। कोविड-19 के मद्देनजर सीबीएसई ने पिछले साल शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नौवी से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम को 30 फीसद तक कम कर दिया था। जिन छात्रों ने घटे हुए पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई की, वे मई-जून में परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे।-एजेंसी

Badri Gautam

चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू

भोपाल। उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक परीक्षा में चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुरुवार को सत्यापन के लिए जिला शिक्षा कार्यालय में 10 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। सत्यापन प्रक्रिया शनिवार को भी की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय(डीपीआइ) द्वारा जारी सूची के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के दस्तोवेजों का सत्यापन तीन, पांच, आठ, नौ व 10 अप्रैल को किया जाएगा, जबकि माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों के सत्यापन की तारीख 15, 16, 17, 22, 23 व 24 अप्रैल रहेगी। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि एक दिन में 10 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। सत्यापन का समय दोपहर एक से शाम पांच बजे तक रहेगा। सत्यापन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। ज्ञात हो कि, डीपीआइ ने एक जनवरी 2020 से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की थी, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15 हजार और माध्यमिक शिक्षक के 5670 पदों पर भर्ती होनी थी। एक जुलाई 2020 से चयन एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी शुरू हुआ, जो तीन जुलाई 2020 तक जारी था, लेकिन कोरोना के कारण प्रक्रिया रोक दी थी। -(नप्र)

Badri Gautam

स्नातक अंतिम वर्ष की आफलाइन परीक्षा अगले माह

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसमें प्रदेशभर के सारे विश्वविद्यालय को अप्रैल में होने वाली यूजी-पीजी कोर्स की परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है जबकि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कोरोना की स्थिति की समीक्षा होगी। उसके बाद ही परीक्षा मई में करवाई जा सकेंगी। वैसे मई के पहले सप्ताह तक विभाग ने नया टाइम टेबल जारी करने पर जोर दिया है। हालांकि यूजी फर्स्ट-सेकंड ईयर की जून में ओपन बुक परीक्षा रहेगी।

संक्रमण के बीच आफलाइन परीक्षा का विरोध किया गया। छात्र संगठनों ने तर्क दिया है कि कोरोना बढ़ने से परीक्षा के दौरान विद्यार्थी भी संक्रमित हो सकते हैं। लगातार कई दिनों तक विरोध के बाद उच्च शिक्षा मंत्री डा. मोहन यादव ने ट्वीट कर परीक्षा आगे बढ़ाने की बात कहीं। गुरुवार को विभाग ने आदेश निकाला, जिसमें यूजी फाइनल ईयर और पीजी चौथे सेमेस्टर की मई में आफलाइन परीक्षा लेना है। बीए, बीकाम और बीएससी फर्स्ट-सेकंड ईयर और एमए, एमकाम, एमएससी की सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा ओपन बुक से करवाने के निर्देश दिए। परीक्षा नियंत्रक डा. अशेष तिवारी का कहना है कि परीक्षा को लेकर लिखित आदेश मिल चुका है। अप्रैल में कोरोना की स्थिति देखने के बाद विभाग को अवगत कराएंगे। साथ ही परीक्षा के बारे में मार्गदर्शन लेंगे। चर्चा के बाद ही परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। पंद्रह दिनों के भीतर परीक्षा संचालित की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा आगे बढ़ने से अगला सत्र भी प्रभावित हुआ है। इसके लिए मूल्यांकन केंद्र को परीक्षा की तुरंत कापियां जांचने के निर्देश दिए हैं।

350 करोड़ के बजट पर चर्चा के लिए विवि कार्यपरिषद की बैठक दो सप्ताह में

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का बजट मंजूर होना शेष है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने अगले सप्ताह बैठक बुलाने का फैसला किया है। मगर कुछ सदस्यों ने ही सहमति दी है। माना जा रहा है कि बजट मंजूर नहीं होने से विश्वविद्यालय में काम अटक गए हैं। इन दिनों कोरोना संक्रमण बढ़ने से अभी तक बैठक नहीं रखी गई है।

10 मार्च को विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यपरिषद की बैठक से महज पंद्रह मिनट पहले बजट की कापी सदस्यों को दी थी। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-21 के लिए 355.18 करोड़ रुपये का बजट बनाया। करीब 24 करोड़ रुपये घाटे का अनुमान लगाया। बैठक में सदस्यों ने भले ही बजट प्रस्तुत करवा दिया, लेकिन विश्लेषण के लिए समय मांगते हुए दो सप्ताह में अगली बैठक रखने को कहा। ज्यादातर सदस्यों ने बजट अगली बैठक में मंजूर करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि बजट अचानक दिया गया है। सोचने-समझने के लिए एक भी सदस्य को समय नहीं मिला। वैसे 10 मार्च की बैठक में बजट से जुड़े सिर्फ नियमित खर्चों को ही मंजूरी दी गई थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि मार्च अंत तक पूरा बजट मंजूर हो जाएगा, लेकिन कोरोना के कारण बैठक नहीं रखी गई।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ● फाइल फोटो

विश्वविद्यालय सालाना बजट को लेकर गंभीर नहीं : कार्यपरिषद सदस्य डॉ. विश्वास व्यास का कहना है कि विश्वविद्यालय सालाना बजट को लेकर भी गंभीर नहीं है। पिछली बैठकों के कई मुद्दे भी अब तक अमल में नहीं लाए गए। इसमें हेड रोटेशन, मूल्यांकन केंद्र के ओएसडी के बदलाव, प्रोफेसरों को दिए गए प्रशासनिक काम आदि शामिल हैं। अब अगली बैठक में इन मुद्दों पर विवाद की स्थिति बन सकती है।

कोरोना के कारण समय लग गया : कुलपति डा. रेणु जैन का कहना है कि कोरोना के कारण कार्यपरिषद की बैठक बुलाने में समय लग गया है। अब अप्रैल दूसरे या तीसरे सप्ताह में बैठक बुलाई जाएगी। इसमें सिर्फ बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।

Badri Gautam

जवाब तलब | हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब के लिए दी मोहलत, एक सीट खाली रखने के दिए निर्देश

अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों को भर्ती के लिए क्यों किया अयोग्य

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने के लिए कहा कि उच्च शिक्षक भर्ती की चयन परीक्षा में चयनित होने के बावजूद अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को क्यों अयोग्य घोषित किया गया?

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि याचिकाकर्ता का नाम मेरिट में होने की दशा में शिक्षक की एक सीट रिक्त रखी जाए।

राजगढ़ जिले के ब्यावरा निवासी किशोर कुमार वर्मा की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा दी। परीक्षा का परिणाम 28 अगस्त 2019 को घोषित हुआ। वह ओबीसी अतिथि शिक्षक वर्ग की प्रावीण्य सूची में था। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के वक्त अचानक 23 जून, 2020 को चयन के लिए बनाए गए नियम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी गई। बदले हुए नियमों के तहत दो जुलाई, 2020 को आदेश जारी कर कहा गया कि अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वालों को चयन प्रक्रिया के अयोग्य समझा जाएगा। ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद कर दी जाएगी। अधिवक्ता तिवारी ने तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया के बीच इस तरह से नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए आग्रह किया कि उक्त नोटिफिकेशन व इसके तारतम्य में जारी किया गया आदेश निरस्त किया जाए। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने 12 अक्टूबर, 2020 को राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। नोटिस का जवाब पेश करने के लिए गुरुवार को कोर्ट से समय मांगा गया।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

हाई कोर्ट ने कहा – राष्ट्रीय आयोग का निर्णय नहीं आया, इसलिए नहीं कर सकते हस्तक्षेप

● **जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।** मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी, जबलपुर में पदस्थ चीफ इंजीनियर एससी वर्मा के जाति प्रमाण पत्र को कठघरे में रखने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने साफ किया कि अब तक धरगर व धनगढ़ जाति को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का निर्णय सामने नहीं आया है, इसलिए हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप की नहीं कर सकता। जगदंबा कॉलोनी, जबलपुर निवासी आरटीआइ एक्टिविस्ट अभिषेक कुमार सिंह ने याचिका दायर की थी।

उनका तर्क था कि चीफ इंजीनियर वर्मा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिये नौकरी हासिल की है। लिहाजा, जाति प्रमाण पत्र की जांच के निर्देश जारी किए जाएं। वर्मा की नियुक्ति 10 जुलाई, 1992 को असिस्टेंट इंजीनियर बतौर हुई थी। उसने नियुक्ति के समय धनगर जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में उसे नौकरी मिल गई। धनगर जाति 19 नवंबर, 1984 को प्रकाशित सूची में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। चीफ इंजीनियर वर्मा के एक रिश्तेदार सुरेश कुमार धनगर ने पीडब्ल्यूडी में सहायक ग्रेड-दो के रूप में नियुक्ति हासिल कर ली थी। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो उसने पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 में चीफ इंजीनियर वर्मा के खिलाफ शिकायत की गई थी। राष्ट्रीय आयोग ने जांच शुरू की, तो वर्मा ने गलत जानकारी पेश कर स्थगन हासिल कर लिया था।

Badri Gautam

270 कालेजों से 250 आवेदन!

दिव्यांग छात्रवृत्ति ● परिवार की आय डेढ़ लाख से ज्यादा तो लाभ नहीं

कपिल नीले . नईदुनिया प्रतिनिधि

विकलांग और दुर्घटना सहायता के तहत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जल्द मिलने की उम्मीद है। 2020-21 सत्र की छात्रवृत्ति के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमानुसार अब आवेदक को परिवार की आय और जिला अस्पताल से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय के अनुसार जिन विद्यार्थियों के परिवार की आय डेढ़ लाख से ज्यादा है, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। दस्तावेजों की जांच के लिए समिति बनाई गई है। सत्यापन के बाद छात्र-छात्राओं के महाविद्यालयों में राशि आवंटित की जाएगी। यहां से आवेदक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार आवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण पांच अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा।

कोरोना के कारण पिछड़े शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आवेदन जनवरी तक बुलवाए गए। 270 महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 250 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है। यह आंकड़ा पिछले सत्र की तुलना में दोगुना से ज्यादा है। विश्वविद्यालय के अनुसार सत्र 2019-20 में महज 108 आवेदन आए थे। नियमों में सख्ती बरती जा रही है। अधिकारियों के अनुसार दिव्यांगों के लिए दो श्रेणियों में छात्रवृत्ति रखी है। 50 फीसद से कम दिव्यांग छात्र-छात्राओं को साढ़े सात हजार रुपये प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे, जबकि 100 फीसद दिव्यांगों को 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदकों को जिला अस्पताल से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा छात्र-छात्राओं को कलेक्टर व तहसील कार्यालय से जारी परिवार की आय का प्रमाण पत्र भी देना है।

छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष डा. एलके त्रिपाठी ने बताया कि 250 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। कुलपति के निर्देश पर समिति बनाई गई है। वह प्राप्त आवेदनों के सूक्ष्म परीक्षण और सत्यापन में जुटी है। 15 अप्रैल तक विद्यार्थियों को राशि आवंटित की जाएगी।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

- **समिति कर रही प्राप्त आवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण और सत्यापन**
- **5 अप्रैल तक हो सूक्ष्म परीक्षण पूरा हो जाने की उम्मीद**

ये है आवेदन की संख्या

वर्ष	दिव्यांग	दुर्घटना
2016	32	22
2017	38	33
2018	43	30
2019	56	47
2020	51	59

आए सिर्फ दो आवेदन

दिव्यांगों के अलावा विश्वविद्यालय दुर्घटना सहायता देगा। सत्र 2020-21 में महज दो आवेदन मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के कारण महाविद्यालयों में कक्षाएं नहीं लग रही हैं। विद्यार्थी घर बैठे आनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इसके कारण दुर्घटनाएं कम हुई है, जिसे आवेदन की संख्या में कमी आई है। पिछले साल 15 से ज्यादा विद्यार्थियों को दुर्घटना सहायता राशि दी गई थी। दुर्घटना सहायता राशि के लिए अस्पताल की मेडिकल चेकअप और डाक्टर का पर्ची व जिला अस्पताल की रिपोर्ट शामिल है।

Badri Gautam

दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) की ओर से पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों का नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में नया सत्र प्रारंभ नहीं हो सका। इस कारण इस बार भी आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई शुरू की

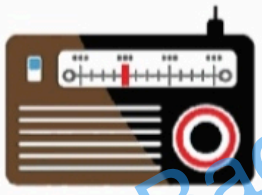

गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने आनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में विशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

रेडियो पर सुबह 10 से 11 और शाम पांच से 5:30 बजे तक एवं दूरदर्शन पर दोपहर 12 से 1: 30 बजे तक आनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। प्राचार्यों के मुताबिक विद्यार्थियों को कार्यक्रम के संबंध में फोन व एसएमएस से जानकारी दी गई है। ऐसे विद्यार्थी जिनके घर टीवी या रेडियो नहीं हैं, उनके लिए जनपद पंचायत में व्यवस्था की गई है। छठी से आठवीं के लिए विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान में विषय आधारित शिक्षण कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है।

रोज निर्धारित समय पर होगा प्रसारण

इसी तरह रेडियो पर पहली से आठवीं के लिए पाठ्यपुस्तक आधारित हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों में और सायंकालीन प्रसारण में खेल, योग, कला, म्यूजिक, यातायात नियम जैसे विषयों पर कार्यक्रम शुरू किए गए। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने बताया यह कार्यक्रम रोज इसी समय पर प्रसारित किए जाएंगे।

Badri Gautam

अगली कक्षा में प्रमोट करने की अंतिम तिथि 15

भोपाल। सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं निजी अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थी की अर्हता का परीक्षण कर स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के पोर्टल पर प्रमोट बॉक्स पर क्लिक कर विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रावधिक प्रवेश के लिए प्रमोट करने के निर्देश जारी किए गए थे। नवीनीकरण के लिए प्रमोट करने की तिथि में एक बार पुन: वृद्धि करते हुए 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। विद्यार्थी 20 अप्रैल तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। -(नप्र)

Badri Gautam

नई गाइडलाइन | एससी पोस्टमैट्रिक स्कालरशिप के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश

दलितों के बच्चों की पढ़ाई में अब नहीं दिखेगी कोई कोताही

नई दिल्ली (ब्यूरो)। अनुसूचित जाति के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए फिलहाल केंद्र सरकार फिक्रमंद है। यही वजह है कि केंद्र ने एससी पोस्टमैट्रिक स्कालरशिप स्कीम की जो नई गाइडलाइन तैयार की है, उनमें शैक्षणिक संस्थानों को अब इन बच्चों को पढ़ाना ही होगा। इस नई गाइडलाइन में वहीं शैक्षणिक संस्थान पात्र भी होंगे, जो गुणवत्ता के तय मानकों को पूरा करेंगे। जिसमें 2024 तक ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों को नैक की मान्यता हासिल करना जरूरी होगा, अन्यथा उन्हें वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। एससी पोस्टमैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के फंडिंग पैटर्न में बड़े बदलाव के बाद केंद्र ने अब नई गाइडलाइन को भी मंजूरी दी है। जिसे सभी राज्यों को अमल के लिए भेजा गया है।

फंडिंग पैटर्न : अब सीधे छात्रों के खाते में भेजी जाएगी छात्रवृत्ति

सरकार ने फंडिंग पैटर्न में भी बदलाव किया है। इसके तहत छात्रवृति का पूरा पैसा अब डीबीटी के जरिए सीधे छात्रों के खाते में भेजा जाएगा। अभी तक यह पैसा राज्यों को दिया जाता था, जो बाद में शैक्षणिक संस्थानों को देते थे। जहां से यह छात्रों को दिया जाता था। इसके साथ ही राज्यों को पहले अपने हिस्से का भुगतान करना होगा।

स्कीम में बड़े बदलाव किए गए

- बच्चों को स्कूल या कालेज आना ही होगा।
- साल में 75 फीसद उपस्थिति जरूरी होगी।
- उपस्थिति आधार कार्ड पर आधारित होगी। इसे संस्थानों को समय-समय पर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

ऐसे हो रही थी गड़बड़ी

अधिकारियों के मुताबिक इस स्कीम के तहत अब तक जो देखने को मिल रहा था, उनमें शैक्षणिक संस्थानों का फोकस छात्रवृत्ति स्कीम के तहत मिलने वाले पैसे को हड़पने पर ही ज्यादा था। इस बीच बड़ी संख्या में ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान और स्कूल तैयार हो गए थे, जहां ऐसे एससी बच्चों को बड़े पैमाने पर प्रवेश दिया जाता था, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी।

लड़कियों के लिए अलग टायलेट और सेनेटरी नैपकिन भी शिक्षा के अधिकार दायरे में : कोर्ट

माला दीक्षित ● नई दिल्ली

छह से चौदह वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार लड़कों और लड़कियों को समान रूप से मिला हुआ है लेकिन कई बार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टायलेट और सेनेटरी नैपकिन आदि न होने से उनके लिए इस अधिकार को सही मायने में प्राप्त कर पाना मुश्किल होता है। इस बात को कर्नाटक हाईकोर्ट ने समझा है और इन मूलभूत सुविधाओं को शिक्षा के अधिकार के दायरे में लाने की बात कही है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह बात सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अन्य सुविधाओं के साथ मुफ्त में सेनेटरी नैपकिन बांटने की कर्नाटक सरकार की शुचि योजना को कड़ाई से लागू करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही।

कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और जे.एम. काजी की पीठ ने आदेश में कहा कि लड़कियों को टायलेट व सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना न सिर्फ उन्हे सशक्त करता है बल्कि छह से चौदह वर्ष की लड़कियों के लिए अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) के प्रविधानों को लागू करने की तरफ एक कदम है।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Badri Gautam

केंद्रीय विद्यालय के कक्षा एक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू

भोपाल। केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा एक में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। भोपाल के पांच समेत देशभर के 1200 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दाखिले का रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव हो गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की वेबसाइट **kvsangathan.nic.in** के जरिए रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल तक किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा। एडमिशन के लिए पहली सूची 23 अप्रैल को जारी होगी। शहर के पांच केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा एक में करीब 150 सीटें हैं। इस लिहाज से भोपाल के पांच स्कूलों में कक्षा एक के लिए 750 सीटें उपलब्ध होंगी। (नप्र)

Badri Gautam

बीई और बीटेक में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 20 जून को

इंजीनियरिंग का कोर्स

- कोमेडके यूजीईटी और यूनीगेज संयुक्त की प्रवेश परीक्षा
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 मई तक जारी रहेगी

भोपाल(नरि)। कोमेडके यूजीईटी और यूनीगेज संयुक्त प्रवेश परीक्षा 20 जून को आयोजित की जा रही है। यह प्रवेश परीक्षा कर्नाटका प्रोफेशनल कॉलेजेस फाउंडेशन ट्रस्ट तथा यूनीगेज के सदस्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों में बीई, बीटेक में प्रवेश के लिए है। भोपाल समेत देश भर के 150 से भी अधिक शहरों में 400 से भी अधिक केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष इस परीक्षा में आठ हजार से अधिक विद्यार्थियों के बैठने की संभावना है। परीक्षा के लिए आवेदकों को www.comedk.org gt www.unigauge.com पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 20 मई तक जारी रहेगी। कोमेडके के एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉ. कुमार ने बताया कि इंजीनियरिंग की शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक हमेशा से एक अग्रणी स्थान रहा है। पिछले 15 सालों से कोमेडके इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इरा फाउंडेशन के सीईओ पी. मुरलीधर ने कहा

कि पिछले वर्ष कोविड महामारी के बावजूद हमने 392 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा में करीब छह हजार विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इस वर्ष सुरक्षा मानकों को और अपग्रेड किया है। हर सेंटर पर सिर्फ 50 प्रतिशत विद्यार्थियों के हिसाब से बैठक व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र सुबह 9 बजे शुरू होकर दोपहर 12 बजे समाप्त होगा, जबकि दूसरा सत्र दोपहर दो बजे प्रारंभ होकर शाम पांच बजे समाप्त होगा।

Badri Gautam

बीएड करने वाले शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य क्यों?

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने के लिए कहा कि उच्च शिक्षक भर्ती की चयन परीक्षा में चयनित होने के बाद भी अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को क्यों अयोग्य घोषित किया गया? मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि याचिकाकर्ता का नाम मेरिट में होने की दशा में शिक्षक की एक सीट रिक्त रखी जाए। ब्यावरा (राजगढ़) निवासी किशोर कुमार वर्मा की ओर से याचिका दायर की गई। उनके अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने कोर्ट को बताया याचिकाकर्ता ने स्कूल शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती परीक्षा दी। इसका परिणाम 28 अगस्त 2019 को घोषित हुआ। वह ओबीसी अतिथि शिक्षक वर्ग की प्रावीण्य सूची में था। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के वक्त अचानक 23 जून, 2020 को चयन के लिए बनाए नियम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी गई। -नप्र

Badri Gautam

जेईई मेन : 27 अप्रैल से होने जा रही है तीसरे चरण की परीक्षा

सफल होने के लिए देते रहें माक टेस्ट

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा जाइंट एंट्रेंस एक्जामिनेशन (जेईई) मेन का तीसरा चरण 27 अप्रैल से शुरू होगा। इसके पहले फरवरी और मार्च में दो चरण की परीक्षा हो चुकी है। इसके परिणाम भी जारी हो चुके हैं। इसमें सफल हुए विद्यार्थियों का कहना है बेहतर स्कोर पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एनसीईआरटी के सिलेबस की लगातार तैयारी की जानी चाहिए। हर दिन माक टेस्ट देना चाहिए।

पिछले दो राउंड में सफल हुए विद्यार्थियों का कहना है कि फरवरी और मार्च में हुई परीक्षा में कई प्रश्न एनटीए के सैंपल पेपर से पूछे गए थे। आगामी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वर्ष से जेईई मेन के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। अब वैकल्पिक प्रश्न भी रहते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के पास च्वाइस बढ़ गई है। प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें से विद्यार्थियों को 75 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। परीक्षा विशेषज्ञ विजित जैन कहते हैं फरवरी और मार्च में हुई परीक्षा में विद्यार्थियों को केमेस्ट्री और मैथ्स के कुछ प्रश्नों में चुनौती मिली थी। हालांकि परीक्षा परिणाम की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार विद्यार्थियों को पैटर्न आसान लगा है।

जेईई एडवांस की तैयारी भी जारी रखें

जेईई मेन के चार चरण पूरे होने के बाद इसमें से बेहतर परीक्षा के अंक को जेईई एडवांस में शामिल होने का आधार माना जाएगा। उम्मीद है 99 पर्सेंटाइल से ज्यादा स्कोर वाले विद्यार्थियों को एडवांस में शामिल होने का मौका मिल सकता है। पिछले दो चरण के परिणाम में जिन विद्यार्थियों को 99 पर्सेंटाइल से ज्यादा स्कोर मिला है उन्हें एडवांस की तैयारी जारी रखनी चाहिए। इस बार जेईई एडवांस में देशभर से करीब 2.45 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें सफल होने वाले विद्यार्थियों को आइआइटी और अन्य टाप संस्थानों में प्रवेश मिलेगा।

Badri Gautam

एनसीसी की परीक्षाएं सात अप्रैल से होंगी

एनसीसी बी सर्टिफिकेट परीक्षा की तारीख बढ़ी

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। कोरोना को देखते हुए डीजी एनसीसी द्वारा एनसीसी कैडेट्स की वी सर्टिफिकेट की परीक्षा की तारीख को तीन व चार अप्रैल से वढ़ा कर सात और आठ अप्रैल कर दिया गया है। जवकि सी सर्टीफिकेट की परीक्षा 9 और 10 अप्रैल को ही ली जाएगी। गौरतलव है कि इस वर्ष कोरोना को देखते हुए कैडेट्स की पढ़ाई के लिए एक एनसीसी एप जारी किया गया था। कैडेट्स ने पूरे साल इसी एप के माध्यम से पढ़ाई की। कैडेट्स के प्रैक्टिकल विषयों की तैयारी के लिए वीते माह शहर में एनसीसी शिविरों का आयोजन किया गया। अलग अलग स्थानों पर आयोजित शिविरों में कैडेट्स को होने वाली परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी कराई गई। अव जवकि एक वार फिर कोरोना का संक्रमण वढ़ने से परीक्षाओं का होना फिर से असमंजस में आ गया है।

शिविरों में कैडेट्स को वताया गया कि परीक्षाओं में 350 अंक की थ्योरी होती है और 150 अंकों का प्रैक्टिकल। इसलिए प्रैक्टिकल से कहीं

ज्यादा जरूरी थ्योरी है। मेजर अरुंधति सी शाह ने वताया कि कैडेट्स को पढ़ने में परेशानी न हो इसलिए एनसीसी एप में एनसीसी के पूरे कोर्स को समाहित किया गया। यहां तक कि जो प्रैक्टिकल के विषय हैं उन्हें भी चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। जिन कैडेट्स ने आनलाइन कक्षाओं के साथ एनसीसी एप के माध्यम से पढ़ाई की है उन्हें परीक्षाओं की तैयारियों में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वल्कि शिविरों में एक तरह से उनके द्वारा की गई पढ़ाई का दोहराव ही होगा। दरअसल, कैडेट्स ने जो पढ़ा है उसे दोहराने के लिए ही इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिससे कैडेट्स अपने जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें। जहां तक कैडेट्स की वात है तो परीक्षाओं की तिथियों को लेकर कैडेट्स परेशान हैं।

Badri Gautam

बाल भवन के विद्यार्थी कर रहे अभिनय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन

बच्चों को मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य के साथ साथ अभिनय का प्रशिक्षण भी दिया गया

Badri Gautam

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। शहर के वच्चों में प्रतिभाओं की कमी नही है। वस जरूरत है तो उन्हें निखारने और संवारने की। ऐसे ही वच्चों के हुनर को निखारने के लिए संभागीय वाल भवन द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। वच्चों को मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य के साथ साथ अभिनय का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। संचालक वाल भवन गिरीश विल्लोरे ने वताया कि वाल भवन जिन वच्चों को अभिनय में रुचि है, उन लोगों ने अभी हाल ही में शहर में हुए एक टी वी चैनल के लिए ऑडिशन दिया। जिसमे कुछ वच्चों का उनके हुनर के आधार पर चयन कर लिया गया है।

इसके अलावा फिल्म निर्माता और सूई धागा, गंगाजल, गांधी वर्सेज गोडसे जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके विकास पांडेय द्वारा वल भवन के वच्चों को अभिनय का प्रशिक्षण निश्शुल्क दिया गया। जिसे वच्चों ने उत्साह से समझा और सीखा। विकास पांडेय ने वताया कि शहर में पिछले कुछ समय से फिल्मों की शूटिंग वढ़ी है और आने समय मे भी कई वड़े वैनर की फिल्मों का निर्माण शहर में किया जाने वाला है। जिसमे वाल कलाकारों की भी जरूरत है। इसलिए अच्छा होगा कि वच्चों को तैयार रखा जाए, जिससे उन्हें वड़े वैनर की फिल्मों में काम करने का अवसर मिल सके। विकास चाहते हैं कि शहर की प्रतिभाओं को फिल्मों में अवसर मिले। इसलिए वे वच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

इसके लिए वाल भवन से भी वहुत सहयोग मिल रहा है। वच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी सहयोग दे रहे हैं। वच्चों को सिखाना इसलिए भी आसान ही क्योंकि वो कोरे कागज की तरह होते हैं। जैसा वताओ वैसा ही वड़े समपर्ण और लगन से करते हैं। जिस तरह से वच्चों का चयन हुआ है उससे हम सभी की उम्मीद और वढ़ी है।

आकांक्षा योजना के तहत चयन परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल

भोपाल। आकांक्षा योजना के अंतर्गत मप्र के मूल निवासी अजजा वर्ग के छात्र-छात्राओं को, जिन्होंने 10 वीं में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, जेईई, एनईईटी, एआईएमएस, सीएलएटी की तैयारी के लिए जबलपुर, इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर में द्विवर्षीय कोचिंग प्रदान की जाएगी। सत्र 2021-22 की आकांक्षा योजना की चयन परीक्षा के लिए पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 7 अप्रैल कर दी गई है। चयन परीक्षा के लिए पोर्टल पर 7 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है।

योजना

Badri Gautam

अगली कक्षा में प्रमोट करने 15, फीस के लिए 20 अप्रैल तक अंतिम मौका

भोपाल। शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं निजी अशासकीय कॉलेजों द्वारा स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा पीजी तृतीय सेमेस्टर के लिए संबंधित विवि के पोर्टल पर प्रमोट बाक्स में क्लिक कर विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्राविधिक प्रवेश के लिए प्रमोट करने के निर्देश जारी किए गए थे। यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार, नवीनीकरण के लिए प्रमोट करने की तिथि में फिर वृद्धि करते हुए यह 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। विद्यार्थी 20 अप्रैल तक ऑनलाइन शुल्क जमा करने की कार्यवाही कर सकते हैं।

एजुकेशन

BadriGautam

दूरदर्शन व आकाशवाणी के माध्यम से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) की ओर से पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों का नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में नया सत्र प्रारंभ नहीं हो सका। इस कारण इस बार भी आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई शुरू की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने आनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। रेडियो पर सुबह 10 से 11 और शाम पांच से 5.30 बजे तक एवं दूरदर्शन पर दोपहर 12 से 1: 30 बजे तक आनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। प्राचार्यों के मुताबिक विद्यार्थियों को कार्यक्रम के संबंध में फोन व एसएमएस से जानकारी दी गई है। ऐसे विद्यार्थी जिनके घर टीवी या रेडियो नहीं हैं, उनके लिए जनपद पंचायत में व्यवस्था की गई है। छठी से आठवीं के लिए विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान में विषय आधारित शिक्षण कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है।

Badri Gautam

अमृत महोत्सव की राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में हिंदी विवि तीसरे नंबर पर

उपलब्धि

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में हिंदी विश्वविद्यालय की स्टूडेंट श्वेता शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। विवि के कुलपति प्रो. रामदेव भारद्वाज, कुलसचिव यशवंत पटेल एवं समस्त विभागाध्यक्षों ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है।

Badri Gautam

शिक्षक विनोद के सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई

स्टार समाचार अमदरा

शिक्षक संघ के वरिष्ठ सदस्य विनोद कुमार शुक्ला शिक्षक जो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सभागंज में पदस्थ थे। 31 मार्च को अपनी अधिवार्षिक आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर स्कूल में आयोजित विदाई सम्मान समारोह में विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती किरण चौरिहा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं।

इस अवसर पर श्रीमती चौरिहा ने कहा कि श्री शुक्ला हमेशा ड्यूटी के पाबन्द थे। समय से स्कूल आते थे हमेशा ही सहयोग उनका मिला। बहुत ही मिलनसार थे यह पल सबके साथ एक न एक दिन आता ही है।

वहीं विनोद शुक्ला ने कहा कि हमेशा पूरा सहयोग स्टाफ से मिला। मेरा यह एक परिवार था जब इंसान परिवार से अलग होता है तो दुख होना स्वभाभिक ही है यह दिन हर कर्मचारी के पल में आता है जब अपनों के बीच होने के बाद अलग होते हैं तो वह पल बहुत ही दुखदाई लगता है जो प्यार व अपनापन स्टाफ व बच्चों से मुझे मिला है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता।

श्री शुक्ला को शाल श्रीफल व प्रतिमा व अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जयपाल सिंह ने किया जबकि राम सुजान पांडेय, सेवालाल यादव व स्टाफ के लोग, विद्यायल के छात्र-छात्राएं की उपस्थिति रही।

Badri Gautam

रिक्त पदों पर स्थाई शिक्षकों की भर्ती की मांग

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूल शिक्षा विभाग 24,200 रिक्त पदों पर स्थाई शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में स्थाई शिक्षकों की भर्ती के लिए फरवरी-मार्च 2019 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी पिछले वर्ष कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रिया को बीच में ही स्थगित कर दिया गया था 1 अप्रैल 2021 से उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए सत्यापन प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया गया है। शिक्षक पात्रता संघ के प्रदेश संयोजक रंजीत गौर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 24,200 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए इस सत्र में बजट पारित किया है परंतु लोक शिक्षण संचालनालय उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 15,000 एवं माध्यमिक शिक्षकों के 5,670 पदों को मिलाकर कुल 20,670 पदों पर स्थाई शिक्षक भर्ती करने जा रहा है।

Badri Gautam

महाविद्यालयों में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित

विदिशा। सत्र 2020.21 के अंतर्गत स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेषित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन के समय मूलए डुप्लीकेट टीसी माईग्रेशन ही संबंधित विद्यार्थी से प्राप्त किए जाएं। अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति महाविद्यालय में जमा नहीं कराई जाएं। यदि संबंधित विद्यार्थी से निर्धारित समय सीमा में मूलए डुप्लीकेट टीसी माईग्रेशन प्राप्त नहीं होते हैए तो दिए गए निर्देशानुसार एक माह में जमा करने संबंधी वचन पत्र के आधार पर प्रवेश मान्य किया जाएं। इस आशय के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने समस्त शासकीय अग्रणीए शासकीय अनुदान एवं निजी महाविद्यालयों को दिए है। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन ई.प्रवेश समय.सारिणी सत्र 2020.21 सीएलसी षष्ठम चरण के परिप्रेक्ष्य में टीसी माईग्रेशन एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराकर दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

Badri Gautam

कक्षा 1 से 8 के छात्रों हेतु दूरदर्शन व रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम फिर शुरू

नवीन शैक्षणिक सत्र 2021.22 में कक्षाओं का ऑनलाइन संचालन जारी रहेगा

वैढ़न (नव स्वदेश)। स्कूल शिक्षा विभाग कक्षा पहली से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए 1 अप्रैल से पूर्वानुसार ही दूरदर्शन और रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण कर दिया गया है। रेडियो पर यह शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रातः 10 से 11 और सांय 5 से 5रू30 बजे तक एवं दूरदर्शन पर दोपहर 12 से 1.30 बजे तक संचालित की जाएंगी। दूरदर्शन पर कक्षा छठवीं से आठवीं के लिए विज्ञानए गणित एवं सामाजिक विज्ञान में विषय आधारित शिक्षण कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

इसी प्रकार रेडियो पर कक्षा पहली से आठवीं के लिए पाठ्यपुस्तक आधारित हिंदीए गणितए अंग्रेजी विषयों में और सांयकालीन प्रसारण में खेल योग कला म्यूजिक यातायात नियम जैसे विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।उल्लेखनीय है कि डिजीलेप अर्थात डिजिटल लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कक्षा पहलीए दूसरी के पाठ्यपुस्तक आधारित वीडियो तथा कक्षा तीसरी से आठवीं के लिए दक्षता उन्नयन गतिविधि आधारित वीडियो प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकोंए पालकों और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

शिक्षकों के द्वारा इन वीडियो पर क्विज प्रश्न आदि से सीखे गए विषयों के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। कोविड 19 वायरस की वर्तमान परिस्थितियों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर नवीन शैक्षणिक सत्र 2021.22 में कक्षाओं का ऑनलाइन संचालन किया जाएगा। सत्र 2020.21 में कोविड.19 के कारण कक्षा पहली से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं हो सका है। इस कारण संपूर्ण सत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को रेडियो स्कूल, डिजीलैप और दूरदर्शन के माध्यम से आयोजित करके शिक्षण प्रक्रिया जारी रखी गई है। संपूर्ण सत्र को ष्हमारा घर.हमारा विद्यालय की अवधारणा पर पालकों एवं शिक्षकों के सहयोग से शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रखने के प्रयास किए गए हैं।

Badri Gautam

नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को राहत

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 साल बाद आखिरकार उनका वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। वही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 1 महीने तक चलेगी। दरअसल लोक शिक्षण संचनालय द्वारा 2020 में 20670 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रदेश में शासकीय स्कूल में 3 शिक्षकों की भर्ती की पात्रता परीक्षा 2019 फरवरी महीने में शुरू की गई थी।

जिसके बाद कोरोना की वजह से भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। एक बार फिर से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। वही नियुक्ति के लिए 2 साल बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब शिक्षकों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। शिक्षकों का वेरिफिकेशन कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक किया जा रहा है। बता दे कि पहले दिन 10 शिक्षकों का वेरिफिकेशन हुआ। वही प्रतिदिन 20 शिक्षकों का वेरिफिकेशन किया जाएगा।

ज्ञात हो कि प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के लिए 12000 शिक्षकों का और शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए 7000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। वहीं इससे पहले सरकार द्वारा विधानसभा में 24,200 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए बजट

पारित किया गया है। लेकिन लोक शिक्षण संचनालय द्वारा केवल 20,670 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की।

जिसके बाद मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवार स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलने उनके पास पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सौंपा है। वही अभ्यर्थियों की मांग है कि 24,200 स्थाई शिक्षकों की भर्ती इसी सत्र में होनी चाहिए। इसके साथ ही रिक्त पदों में वृद्धि की मांग भी अभ्यर्थी द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से की गई है।

Badri Gautam

आदिवासी खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन

भोपाल। जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2021-22 में विभागीय गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिये दैनिक भत्ते-भोजन की दरों में संशोधन किया है। जिला एवं संभागीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों को 115 रूपये दैनिक भत्ता, विभागीय राज्य एवं शालेय शिक्षा स्तर प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों को 130 रूपये और प्री-नेशनल कोचिंग केम्प में सहभागिता करने वाले खिलाड़ी को 200 रूपये दैनिक भत्ते की दर मंजूर की है। इस संबंध में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।

Badri Gautam

बोर्ड परीक्षा पर भी मंडरा रहा कोरोना का साया

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। वजह यह भी है कि लगातार संक्रमण का देखते हुए मंडल अब इन्हें आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि इन परीक्षाओं को लेकर फैसला 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होने वाली समीक्षा बैठक में लिया जाएगा। इससे पहले वह प्रदेश के सभी जिलों में मौजूदा हालातों पर कलेक्टरों से चर्चा करेंगे।

बता दें कि पूर्व में नियत समय सारिणी के मुताबिक 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है। वहीं 9वीं व 11वीं की 13-14 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि विभाग को तय समय पर परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन संक्रमण की स्थिति और बिगड़ती है तो बोर्ड परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार हो सकता है। इस पर 15 अप्रैल के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जबकि 9वीं-11वीं की परीक्षा कैसे कराएं, इसे लेकर विकल्पों पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

- 10वीं-12वीं की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार
- 12 अप्रैल को समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय

Badri Gautam

इसलिये भी है संशय

कोरोना बढ़ने के कारण परीक्षाओं की तैयारी पर असर पड़ा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में 15 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कक्षा 9वीं व 11वीं की लिखित परीक्षाओं की तैयारी भी बाधित हुई है। ऐसे में सरकार दोनों परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से कराने पर विचार कर रही है।

मदद के लिये खुली है मंडल की हेल्प लाइन

कोरोना कॉल में परीक्षा को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों की सहायता के लिये हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए यह सुविधा बीते गुरूवार से 12 घंटे के लिये शुरू हो गई है। यह हेल्प लाइन सेवा 12 घंटे खुली रहेगी। जहां परीक्षा देने वाले विद्यार्थी व उनके पालक, शिक्षक और अन्य लोग टेलीफोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

6 अप्रैल को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से नवाजी जाएंगी डा. अर्चना

स्टार समाचार सतना

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय व्यंकट क्र. 1 में पदस्थ डा. अर्चना शुक्ला आगामी 6 अप्रैल को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 से नवाजा जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा में नवाचार के लिए डा. अर्चना शुक्ला को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित किया गया था। आगामी 6 अप्रैल को जिला मुख्यालय स्थित एनआईसी के वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में अपरान्ह 3 बजे से आयोजित कार्यक्रम में डा. शुक्ला को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा।

Badri Gautam

शिक्षा विभाग में भर्रेशाही, कागजों में चल रही ड्यूटी

सतना। सर्व शिक्षा अभियान के जिला दफ्तर में जमकर भर्रेशाही चल रही है। इसमें मिशन कैप्टन भी भरसक मदद कर रहे हैं नतीजा यह है कि डीपीसी बेलगाम हो गए हैं। मिसाल के तौर पर इस मामले को लें। जनपद शिक्षा केन्द्र मझगवां में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जिला शिक्षा केन्द्र में अटैच कर रखा है। यहीं नहीं जिला मुख्यालय के कार्यालय में इनकी रात्रि में ड्यूटी लगाई है। जबकि यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्यूटी में नहीं आता है हांलाकि कागजों में बकायदा ड्यूटी चल रही है इसका ड्यूटी सर्टिफिकेट भी जारी हो रहा है। बताते हैं कि संविदा में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सत्तारूढ़ दल का नेता है। इसी कारण डीपीसी दबाव में हैं। यह दबाव मिशन कैप्टन तक भी पहुंच रहा है। गौरतलब है कि जनपद शिक्षा केन्द्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजू गौतम कई सालों से जिला शिक्षा केन्द्र में अटैच हैं। अब तक जीतने भी डीपीसी रहे वह भी इनका ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी करने में कोई कोताही नहीं बरती।

Badri Gautam

मण्डल परीक्षा की हुई तैयारी बैठक

शासन के निर्देशानुसार परीक्षा की तैयारियां कराएं : कलेक्टर

स्टार समाचार पन्ना

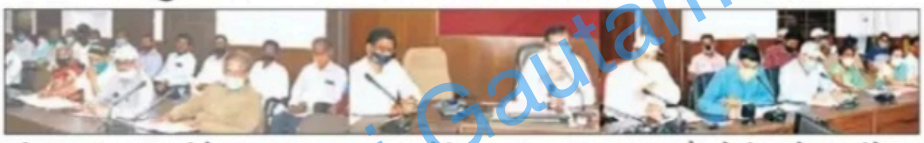

कलेक्टर संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में मण्डल परीक्षा की तैयारियों से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संकुल प्राचार्य एवं संभावित केन्द्राध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में बोर्ड परीक्षा की पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पठन-पाठन की समीक्षा के उपरांत परीक्षा की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गयी। बैठक में परीक्षा केन्द्रों में बैठक व्यवस्था अन्तर्गत फर्नीचर की व्यवस्था पर चर्चा के उपरांत फर्नीचर की कमी होने पर आसपास के शासकीय/अशासकीय स्कूलों से फर्नीचर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। पठन-पाठन के अन्तर्गत डिजीटल शिक्षण माध्यम से कराई गयी पढाई के संबंध में चर्चा की गयी। कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों की दो घण्टे की कक्षाएं आयोजित कर छात्र-छात्राओं की समस्या का समाधान किया जाए।

लोक शिक्षण माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पोर्टल पर ब्लू प्रिंट एवं आदर्श प्रश्न बैंक प्राचार्यों द्वारा डाउनलोड कर छात्रों को वितरित किए जा रहे हैं। परीक्षा केन्द्रों के लिए केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों का चयन किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा रेण्डमाईजेशन के माध्यम से ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी परीक्षा केन्द्रों में कोविड-19 गाइड लाइन अनुसार व्यवस्थाएं की गयी हैं। हांथ धुलाने, निर्धारित दूरी पर बैठाने एवं मास्क लगाने की अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षा केन्द्र में एक कक्ष में आइसोलेशन की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति स्वीकृति में शेष रहे वह तीन दिवस के अन्दर स्वीकृत कर दी जाए। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की विकासखण्डवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि इनका निराकरण समयसीमा में किया जाए। सम्पन्न हुई बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी के.एस. कुशवाहा, जिला परियोजना अधिकारी व्ही.के. त्रिपाठी, योजना अधिकारी के.के. सोनी, सभी विकासखण्ड अधिकारी के साथ अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Badri Gautam

कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को तीन हजार ही देना होगी फीस

जांच करने पहुंचा दल।

कोरोना काल की पूरी फीस वसूली की शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे शिक्षा अधिकारी

निज संवाददाता-

मुंगावली। नगर के निजी विद्यालय माँ कान्वेंट स्कूल के संचालक पर कोरोना काल के समय की पूरी फीस वसूलने के परिजनों के आरोप के बाद गुरुवार को शिक्षा विभाग के अधिकारी माँ कान्वेंट स्कूल पहुंचे। इस दौरान परिजन और स्कूल संचालक के बीच फीस सहमति को लेकर करीब दो घंटे तक बैठक चली। जहां परिजनों और स्कूल संचालक ने अपनी-अपनी बात रखी। परिजनों का कहना था कि जब कोरोना काल के दौरान स्कूल संचालित ही नहीं हुआ तो हम से फीस किस बात की मांगी जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कई परिजनों एसडीएम कार्यालय में पहुँचकर माँ कॉन्वेंट स्कूल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। इन परिजनों द्वारा कहा गया कि वह पहले भी इस स्कूल संचालक की मनमानी की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से कर चुके है। जहां इनके द्वारा कोरोना काल के समय की भी स्कूल फीस वसूल की जा रही है। जबकि किसी भी तरह की पढ़ाई पूरे साल इनके स्कूल में नहीं कराई गई है। इसी मामले को लेकर इन तमाम परिजनों एसडीएम राहुल गुप्ता को एक ज्ञापन भी सौंपा था जिसके बाद एसडीएम ने बीईओ को निर्देशित किया था कि स्कूल संचालक और परिजनों को बैठाकर बात की जाए और यदि इसके बाद भी इस तरह की वसूली की जा रही है तो उचित कार्रवाई की जाए। इन निर्देशों के बाद ही गुरुवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा स्कूल संचालक और परिजनों को बैठाकर चर्चा की गई। जिसके बाद निष्कर्ष निकाला कि पिछले सत्र की 1 से 8 तक के छात्रों की 3 हजार रुपए ही लिए जायेगें और जिनसे अधिक फीस जमा करा ली गई है वह अगले सत्र में समायोजित की जाएगी।

Badri Gautam